वर्ष : 17 | अंक : 142 | मूल्य : 02 रुपया मात्र | पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

शुक्रवार 13 मार्च 2026

शांति बनाए रखें और पैनिक न करें : पीएम

कोरोना महामारी के दौर का उदाहरण देकर कहा कि इस संकट से उबर जाएंगे

एजेंसी। नई दिल्ली

देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर फैली अफवाहों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से शांति बनाए रखने और पैनिक न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण ऊर्जा की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, लेकिन हमारी सरकार संकट से निपटने में सक्षम है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में एनडीए की मीटिंग के दौरान सभी से सही जानकारी साझा करने और बिना पुष्टि के अफवाहें न फैलाने का आग्रह किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एलपीजी सप्लाई पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए हैं। मंत्रालय का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले की तरह जारी है और पैनिक खरीद से स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में जिला प्रशासन लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह दे रहा है। केंद्र सरकार ने पहले ही एस्मा लागू किया है, इसके तहत घरेलू गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है और बीते छह महीनों के औसत के अनुसार सप्लाई बनाए रखने का निर्देश है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर फैक्ट चेक करने और सही

सूचना देने का काम शुरु कर दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और अफवाहों से उत्पन्न हालात को संभालने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौर का उदाहरण देकर कहा कि तब 140 करोड़ भारतीयों ने देश की मजबूती दिखाई थी और अब भी हम इस संकट से जल्द ही उबर जाने वाले है। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना है और किसी भी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। जनता से अपील की गई है कि केवल सत्यापित सूचना को साझा करें और अफवाहों को आगे न बढ़ाएं। इस तरह, प्रशासन और केंद्र सरकार मिलकर एलपीजी संकट को नियंत्रित करने और लोगों को सही जानकारी देने में सक्रिय हैं।

गैस की किल्लत से दिल्ली के 12 रेस्टोरेंट बंद, 5 हजार का मिल रहा एक सिलेंडर

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण सैन्य संघर्ष की तपिश अब देश की राजधानी दिल्ली की रसोई तक पहुंच गई है। वैश्विक तनाव के कारण ईंधन की आपूर्ति बाधित होने से दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी कमी के चलते बुधवार को दिल्ली के कम से कम 12 प्रमुख रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों को अस्थायी रूप से अपने शटर गिराने पड़े। सीमित सप्लाई के कारण कई अन्य संचालक भी अपने किचन को चालू रखने के लिए भारी मशक्कत कर रहे हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि ब्लैक में एक सिलेंडर की कीमत 5 हजार रुपए चुकाना पड़ रही है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडरों का स्टॉक बेहद कम मात्रा में मिल रहा था, जो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। स्टॉक समाप्त होने के कारण कई प्रसिद्ध आउटलेट्स को अपना संचालन बंद करना पड़ा है।

पश्चिम एशिया युद्ध से गैस संकट पर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन

नई दिल्ली। पश्चिमी एशिया में अमेरिका-इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से उत्पन्न गैस संकट को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राजीव शुक्ला, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत 200 से अधिक सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने हाथों में बड़े-बड़े पोस्टर और गैस सिलेंडर के कटआउट लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की। पोस्टरों पर सिलेंडर की तस्वीरें थीं और उन पर गैस संकट से जुड़ी मांगें लिखी थीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युद्ध के कारण गैस वितरण प्रभावित हो रहा है और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस प्रदर्शन की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि पूरे भारत में एलपीजी की कमी के कारण लंबी कतारें लग रही हैं। करोड़ों नागरिक खाद्य सुरक्षा संकट का सामना कर रहे हैं, छोटे-छोटे भोजनालय बंद हो रहे हैं और लोगों में व्यापक भय फैल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरी तरह असहाय साबित हुए हैं और उनकी सरकार इस संकट से निपटने में नाकाम है। विपक्षी सांसदों ने संसद में प्रदर्शन कर सरकार की अक्षमता को उजागर किया और तत्काल समाधान की मांग की। वहीं दूसरी तरफ, संसद के बजट सत्र में पूरे सत्र के लिए निष्कासित किए गए विपक्ष के आठ सांसदों ने भी संसद भवन परिसर स्थित मकर द्वार पर गैस संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मायने

हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर सदन मे सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों ने चर्चा कर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना-अपना मत रखा है। भारतीय संसद की कार्य प्रणाली और संसदीय परंपराओं को लेकर गंभीर बहस हुई है। पिछले 7 वर्षों से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी खाली पड़ा हुआ है। इस पर भी विपक्षी दल के सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का नेता माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से बोलने नहीं दिया गया था। सदस्यों को बोलने के दौरान बार-बार टोंका जाता है। तरह-तरह के नियम बताकर सांसदों को अपनी बात नहीं कहने दी जाती है। बिना चर्चा और बिना प्रक्रिया के सदन से जो बिल पास किये जा रहे हैं। सत्र की अवधि लगातार कम किए जाने के कारण सदस्य अपनी बात संसद में नहीं रख पाते हैं इसको लेकर संसद सदस्यों में पिछली कई वर्षों से नाराजी देखने को मिल रही थी।

सत्ता पक्ष जिस तरह से विपक्षी सदस्यों को बोलने से रोकता था आसंदी का सत्ता पक्ष के लिए अलग व्यवहार और विपक्ष के लिए अलग व्यवहार अविश्वास प्रस्ताव का कारण बना। लोकसभा अध्यक्ष का पद संविधान और संसदीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष सभी सदस्यों का संरक्षक होता है। वह सरकार या किसी पार्टी का नहीं होता है। यह पद सदन की कार्यवाही निष्पक्ष और संतुलित ढंग से संचालित हो। सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार मिले। जो भी कानून और नियम बनाए जा रहे हैं उनमें सभी पक्षों की राय ली जाए। यह दायित्व लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। सदन में किसी भी विषय पर स्वतंत्रता से संसद सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। यदि कुछ नियमों के विपरीत होता है तो उसे हटाने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होता है लेकिन बोलने के पहले ही उसे रोक दिया जाए।

पिछले 12 वर्षों में यह बहुत बार देखने को मिला है। यही अति अविश्वास का सबसे बड़ा कारण बनी। सत्ता पक्ष बहुमत में होता है। विपक्ष अल्पमत में होता है। ऐसी स्थिति में यह परंपरा रही है कि अध्यक्ष सरकार और विपक्ष के बीच जब टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में वह मध्यस्थता करके तथा अपने अधिकारों का उपयोग करके सही निर्णय लेकर सदन की कार्रवाई को संचालित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पिछले कुछ वर्षों से सत्ता पक्ष का दबाव आसंदी पर देखा जा रहा था। ऐसे में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल एक व्यक्ति पर सवाल नहीं बल्कि संसद की कार्यशैली और लोकतांत्रिक संवाद और जवाबदेही का भी मामला है।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत में जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा का भी उठाया मुद्दा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के हालात के बीच ईरान के

विदेश मंत्री से अब तक तीन बार बातचीत की। इसमें भारतीय जहाजों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में एक सवाल पर कहा, "पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच तीन बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से सबसे ज्यादा तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके चलते देश में गैस की उपलब्धता में कमी आई है। वहीं बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों के लिए परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। हमें बांग्लादेश सरकार से डीजल की आपूर्ति के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ संबंधों के प्रति हमारे जनकेंद्रित और विकास-उन्मुख दृष्टिकोण को देखते हुए हम 2007 से नुमालीगढ़ रिफाइनरी से विभिन्न माध्यमों: जलमार्ग, रेल और बाद में भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइप-लाइन के माध्यम से डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2017 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हाई-स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक बिक्री-खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

वायु सेना प्रमुख ने फ्रंटलाइन फाइटर बेस से मिग-29 यूपीजी में अकेले उड़ान भरी

नई दिल्ली। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने वायु सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को पश्चिमी एयर कमान के तहत फ्रंटलाइन फाइटर बेस से उड़ान भरी। उन्होंने मल्टी-रोल एयरक्राफ्ट मिग-29 यूपीजी को अकेले उड़ाया और वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं का आकलन किया। एयर चीफ मार्शल सिंह 5,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने वाले बहुत अनुभवी पायलट हैं, जिन्हें प्रायोगिक परीक्षण पायलट के तौर पर विशेषज्ञता और मिग-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भारतीय वायु सेना ने अपने उन्नत मिग-29 यूपीजी लड़ाकू विमानों को श्रीनगर में तैनात किया है। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी हवाई हमले को देखते हुए यह तैनाती की गई है। इसी के साथ वायु सेना मिग-29 यूपीजी का कुल तकनीकी जीवन (टीटीएल) 10 वर्षों तक बढ़ाने की योजना बना रही है। अभी मिग-29 लड़ाकू विमानों का टीटीएल 40 साल है, जिसे दूसरा जीवन विस्तार देकर 50 साल किये जाने पर विचार किया किया जा रहा है। पहले से ही लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या कम होने और बेड़े में शामिल होने वाले विमानों की धीमी प्रगति को देखते हुए मिग-29 के बेड़े को अधिकतम समय तक सेवा में प्रभावी रखना जरूरी हो गया है।

संसद में कई सांसदों उठाया फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले का मुद्दा, सरकार को घेरा

नई दिल्ली। संसद में कई सांसदों ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व जम्मू-कश्मीर सीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय पुलिस पर नियंत्रण को मुद्दा बनाया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसका खंडन करते हुए इसे एक गंभीर मामला बताया और जांच का आश्वासन दिया। खड़गे ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पहले एक पूर्ण विकसित राज्य था और अब पुलिस केंद्र के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सुरक्षाकर्मियों ने उनकी जान बचाई और पूछा, क्या सरकार का यही इरादा था कि एनसी नेता की हत्या की जाए? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नड्डा ने कहा कि पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला चिंता का विषय और एक गंभीर मामला है और इसकी उचित जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी

को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनसी नेता फारुक अब्दुल्ला की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरुरी कदम उठाए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि हर मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए और सरकार के खिलाफ खड़गे के आरोपों की कड़ी आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान ने भी फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि घटनास्थल पर पुलिस मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी इस घटना में घायल हुए हैं और उन्होंने और अन्य लोगों ने मिलकर अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।

सदन की मर्यादा और परंपराओं को बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी: बिरला

एजेंसी। नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बुधवार को ध्वनिमत से खारिज होने के बाद गुरुवार को अध्यक्ष के आसन पर बैठे। बिरला ने कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर संकल्प आया और इस पर दो दिनों तक 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई। उनका हमेशा प्रयास रहा है कि सदन के भीतर प्रत्येक सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अपने विचार व्यक्त कर सके और सभी को पर्याप्त अवसर मिले। बिरला ने कहा कि यह सदन समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की आवाज बने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रावधान है और इस पावन सदन ने उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष पद का दायित्व दिया। उनका प्रयास रहा है कि सदन की कार्यवाही निष्पक्षता, अनुशासन और संतुलन के साथ संचालित हो। दस फरवरी को विपक्ष के कुछ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था और उन्होंने अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के साथ ही सदन की कार्यवाही से स्वयं को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा कि इस चर्चा के दौरान अनेक विचार, दृष्टिकोण

और भावनाएं सामने आईं और उन्होंने सभी को गंभीरता से सुना। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बिरला ने स्पष्ट किया कि कुछ सदस्यों का मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठकर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन यह किसी को विशेष अधिकार नहीं है। सदन नियमों से चलता है और ये नियम न सरकार ने बनाए हैं, न प्रतिपक्ष ने, बल्कि सदन ने बनाए हैं और सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या मंत्रीगण भी यदि सदन में वक्तव्य देना चाहते हैं तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से अनुमति लेनी होती है। किसी सदस्य को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार नहीं है।

उन्होंने संसदीय परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित कुछ फोटो सदन में रखने चाहे तो स्पीकर ने पहले उन्हें दिखाने का निर्देश दिया और अटल जी ने उसका सम्मान किया। उन्होंने 1958 में भी कई उदाहरण हैं जब बिना स्पीकर की अनुमति दस्तावेज सदन में नहीं रखे गए। बिरला ने कहा कि अध्यक्ष के निर्णय से कोई भी सदस्य सहमत या असहमत हो सकता है, लेकिन नियमों और परंपराओं को लागू करना उनका कर्तव्य है।

भारत की पाक को दो-टूक, परमाणु प्रसार के खराब रिकॉर्ड वाले न दें नसीहत

नई दिल्ली। भारत ने कनाडा के साथ हुए यूरेनियम समझौते पर पाकिस्तान के आपत्ति जताने को खारिज किया है और पड़ोसी को नसीहत दी है कि खराब रिकॉर्ड वाले को नसीहत देने का कोई हक नहीं हैं। वहीं भारत की साख हमेशा से बेदाग रही है और दुनिया भी यह मानती है। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस मामले पर पाकिस्तान के बयान को खारिज करते हैं। परमाणु अप्रसार के संबंध में भारत की साख बेदाग है और वैश्विक समुदाय इसे भली-भांति मान्यता देता है। उन्होंने कहा, "जिस देश का इतिहास गुपचुप तरीके से परमाणु प्रसार करने के पुख्ता सबूतों से भरा हो, वह भला निर्यात नियंत्रण और परमाणु प्रसार के जोखिमों के बारे में उपदेश कैसे दे सकता है? ऐसे बेतुके बयान पाकिस्तान द्वारा अपने ही बेहद खराब रिकॉर्ड से ध्यान भटकाने की एक कोशिश के अलावा और कुछ नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने भारत-कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौते और परमाणु प्रौद्योगिकी सहयोग पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि इस व्यवस्था से भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में विस्तार हो सकता है और वैश्विक परमाणु अप्रसार ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है।

इनकम के आधार पर ओबीसी क्रीमी लेयर का स्टेटस तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि कोई उम्मीदवार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर में आता है या नॉन-क्रीमी लेयर में यह सिर्फ आमदनी के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इनकम ब्रैकेट के आधार पर क्रीमी लेयर का स्टेटस तय करना, पोस्ट की कैटेगरी और स्टेटस पैरामीटर का जिक्र किए बिना, कानून में साफ तौर पर टिकने लायक नहीं है। बता दें "क्रीमी लेयर" में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के ज्यादा अमीर और सामाजिक रूप से आगे रहने वाले सदस्य आते हैं जिन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के दायर से बाहर रखा गया है। यह नियम इंद्रा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया था, लेकिन अमीर तबकों को बाहर रखने का आदेश दिया था। बाद में सरकार ने ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए 1993 में नियम बनाए। अभी, सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाला ओबीसी परिवार आम तौर पर क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाता है और आरक्षण पाने के अयोग्य हो जाता है।

मौत के मुहाने से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सुरक्षित मुंबई पहुंचा भारत का तेल टैंकर

एजेंसी। नई दिल्ली

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ी भीषण जंग ने इस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। विशेष रूप से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) वर्तमान में युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है, जहाँ से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस क्षेत्र में लगातार तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने और उन्हें डुबोए जाने की खबरों के बीच पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट को लेकर हाहाकार मचा है। लेकिन इस भीषण तनाव के बीच भारत ने अपनी सधी हुई और दूरदर्शी कूटनीति के दम पर एक असंभव लगने वाले कार्य को संभव

कर दिखाया है। लाइबेरियाई झंडे वाला विशाल तेल टैंकर शेनलोंग, जो सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर आ रहा था, सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। यह घटना इसलिए असाधारण है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद भारत की ओर आने वाला यह पहला जहाज है, जिसने इस खतरनाक समुद्री रास्ते से निकलकर अपनी मंजिल तय की है। ज्ञात हो कि ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि वह अमेरिका और इजरायल के सहयोग वाले जहाजों को इस मार्ग से गुजरने नहीं देगा। ऐसे में शेनलोंग का सुरक्षित पहुंचना भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। इस सफलता की पटकथा मंगलवार, 10 मार्च को लिखी गई थी, जब भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची से फोन पर लंबी और विस्तृत चर्चा की। ईरान द्वारा केवल चीन के जहाजों को रास्ता देने की घोषणा के बाद, जयशंकर ने मोर्चा संभाला और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती व रणनीतिक स्वायत्तता का हवाला देते हुए भारतीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की।

सीबीआई ने दुबई की फिनटेक प्लेटफॉर्म 'पाईपल' से जुड़ी 900 करोड़ रुपए की ठगी का किया भंडाफोड़, 15 ठिकानों पर छापा

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 15 स्थानों पर छापेमारी की। यह मामला दुबई स्थित फिनटेक प्लेटफॉर्म पाईपल (पीवाईवाईपीएल) के माध्यम से किए गए निवेश और पार्ट-टाइम नौकरी के नाम पर ठगी से जुड़ा है। सीबीआई ने यह मामला गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) से मिले इनपुट के आधार पर दर्ज किया था। आरोप है कि हजारों भारतीय नागरिकों से एक संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने ऑनलाइन योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की। जांच में सामने आया कि नेटवर्क ने सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप और एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाओं

का इस्तेमाल कर लोगों को उच्च लाभ का लालच देकर निवेश के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में छोटे निवेश पर फर्जी मुनाफा दिखाया गया और बाद में बड़ी रकम निवेश कराई गई। एजेंसी ने बताया कि ठगी की रकम तुरंत कई म्यूल (धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फर्जी खाते) बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर कर दी जाती थी ताकि पैसे का स्रोत छिपाया जा सके। इसके बाद रकम को अंतरराष्ट्रीय एटीएम निकासी और विदेशी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, खासकर पाईपल, पर वॉलेट टॉप-अप के जरिए बाहर भेजा जाता था। ये लेन-देन बैंकिंग सिस्टम में प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) ट्रांजैक्शन के रूप में दर्ज होते थे। जांच में दिल्ली-गुरुग्राम सीमा पर बिजवासन गांव के चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक कुमार शर्मा को इस नेटवर्क का सरगना बताया गया है। आरोप है कि उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए म्यूल खातों और विदेशी चैनलों के जरिए बाहर भेजे। ठगी की रकम का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में भी बदला गया। यह भी सामने आया कि शर्मा ने पिछले एक वर्ष में लगभग 900 करोड़ रुपए की रकम 15 शेल कंपनियों के खातों के जरिए दो संस्थाओं से होकर बाहर भेजी। इन संस्थाओं ने रकम को भारत स्थित वर्चुअल एसेट एक्सचेंजों के जरिए यूएसडीटी में बदला और उसे व्हाइट-लिस्टेड वॉलेट्स में ट्रांसफर किया। सीबीआई ने सितंबर 2025 में इन संस्थाओं के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था।

दांडी मार्च की वर्षगांठ संस्कृत सुभाषितम् शेयर कर पीएम मोदी ने सभी विभूतियों को किया याद

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की वर्षगांठ पर इसमें शामिल सभी विभूतियों को याद कर एक संस्कृत सुभाषितम् शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, 1930 में आज ही के दिन दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। इसमें शामिल सभी विभूतियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण। उन्होंने संस्कृत सुभाषितम् लिखा, सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥ इस सुभाषितम् का संदेश है कि सदैव सत्य की ही विजय होती है और असत्य का नाश होता है। इसलिए उस मार्ग का अनुसरण होना चाहिए, जिस मार्ग पर चलकर ऋषियों ने आनंद और परमसत्य की प्राप्ति की। इसके पहले स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय दांडी नमक सत्याग्रह की वर्षगांठ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने महात्मा गांधी को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने पोस्ट किया, 1930 में आज ही के दिन गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह शुरू किया था, इस मार्च ने हर आयु और वर्ग के भीतर स्वतंत्रता की इच्छा को और प्रबल बनाया।

ख़ास ख़बर

मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने धर्म के नाम पर मंदिरों में जानवरों की बलि पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद करने का आदेश दिया। वकील श्रुति बिष्ट ने दायर याचिका में कहा है कि मंदिरों में जानवरों की बलि के मामले पर सरकार और प्रशासन बिल्कुल चुप हैं। याचिका में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट की धारा 28 में जरुरी संशोधन कर धर्म के नाम पर जानवरों की बलि पर रोक लगाने की मांग की गई है। धारा 28 में कहा गया है कि धार्मिक रिवाज के मुताबिक किसी जानवर की बलि लेना अपराध नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि धार्मिक त्यौहारों के समय जानवरों का कत्ल करने पर रोक लगाई जाए। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में बाली, इंडोनेशिया और भारत के हिमालयी इलाके, उत्तर-पूर्वी भारत, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में जानवरों की बलि की परंपरा कायम है। याचिका में मांग की गई है कि इस पर समन्वित रुख अपनाने की जरुरत है, जिसमें मजबूत कानून और एनजीओ वगैरह का सहयोग लेकर जन जागरुकता अभियान चलाना जरुरी है।

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपितों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमानत देने का आदेश दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई, 2022 को पंजाब के मनसा में कर दी गई थी। पवन बिश्नोई और जगतार सिंह पर हत्या के आरोपितों को वाहन उपलब्ध कराने का आरोप है। पंजाब सरकार के वकील ने बिश्नोई की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसके पास वाहन उपलब्ध कराने के लिए सह-आरोपितों की ओर से 41 फोन कॉल्स आए थे। तब पवन बिश्नोई की ओर से कहा गया कि हथियार किसी और ने उपलब्ध कराया था, लेकिन पवन बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। जगतार सिंह पवन बिश्नोई का पड़ोसी है। हत्या के बाद कनाडा का गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बरार भी बिश्नोई गैंग का सदस्य है।

नेताजी बोस की अस्थियां वापस लाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को टोक्यो के रेनकोजी मंदिर से भारत लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुत्री भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में मौजूद थी। याचिका आशीष राय ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी अस्थियों को भारत लाने में नाकाम रही है। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले को कितनी बार उठाया जाएगा। नेताजी देश के सर्वोच्च नेता थे। हम उनके बलिदान का झुककर अभिवादन करते हैं, लेकिन सवाल है कि नेताजी की अस्थियां कहां है, इसके क्या प्रमाण हैं। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नेताजी की बेटी अनीता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुई हैं। तब कोर्ट ने कहा कि अगर वो याचिकाकर्ता होतीं, तो शायद हम इस याचिका पर सुनवाई के बारे में सोच भी सकते थे। हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट आना होगा।

दिल्ली के मटियाला गांव में आग से 400 झुग्गियां जलकर नष्ट

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के मटियाला गांव स्थित मछली मार्केट इलाके में बुधवार देर रात आग लग गयी। देखते ही देखते आग ने आसपास की कम से कम 400 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर दमकल विभाग की नौ गाड़ियां पहुंचीं और ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात करीब 11:54 बजे आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं। आग की गंभीरता को देखते हुए बाद में लगातार और गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। कुल मिलाकर दमकल की नौ गाड़ियां, आठ वाटर बाउजर, दो बीएफटी, दो मोटर पंप, एक हाई टेंडर के साथ कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। शुरूआती जांच के बाद आशंका जताई जा रही है झुग्गियों के पास जमा कूड़े के ढ़ेर में किसी ने सिगरेट या बीड़ी फेंक दी थी, जिससे आग लगी और बढ़कर झुग्गियों तक फैल गई। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रात करीब 12:30 बजे आग को मीडियम श्रेणी की घोषित किया गया। मौके पर डीसीएफओ एके मलिक, डीओ संदीप दुग्गल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और राहत एवं बचाव कार्य का नेतृत्व किया। करीब 2:20 बजे आग को चारों तरफ से घेर लिया गया और 2:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने कूलिंग ऑपरेशन शुरू किया, जो तड़के तक जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग में करीब 400 झुग्गियां, कई दोपहिया वाहन जलकर नष्ट हो गए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है।

24 वर्षों से हर नए कॉरिडोर की पहली मेट्रो यात्रा करने वाले अनिल मारवाह सम्मानित

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य के राज्य मंत्री तोखन साहू ने बुधवार को अनिल मारवाह को विशेष रूप से सम्मानित किया। मारवाह पिछले 24 वर्षों से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के हर नए शुरू होने वाले मेट्रो कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन पहली ट्रेन में सफर करने की अपनी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री टोखन साहू ने मारवाह को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी कहानियां यह दर्शाती हैं कि लोगों का दिल्ली मेट्रो से कितना गहरा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि मेट्रो आज आधुनिक शहरी परिवहन का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में आधुनिक मेट्रो परियोजनाओं की नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान रखी गई थी, जिसके बाद देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। वहीं डीएमआरसी से मिली जानकारी के अनुसार अनिल मारवाह ने वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो की पहली यात्रा से इस अनोखी परंपरा की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक वह हर नए कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन पहली ट्रेन में यात्रा करते रहे हैं। वहीं इस मौके पर मारवाह ने कहा कि दिल्ली मेट्रो ने देश में शहरी परिवहन व्यवस्था को नई दिशा दी है। इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और सड़क यातायात पर निर्भरता भी कम हुई है। उन्होंने कहा कि मेट्रो की समयबद्धता, विश्वसनीयता और सुविधाजनक सेवा के कारण लाखों यात्रियों की यात्रा आसान और तनावमुक्त हुई है।

भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं का संयुक्त प्रयास जरूरी : रविंद्र इंद्राज सिंह

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं का संयुक्त प्रयास जरूरी है। उन्होंने यह बात गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में स्माइल (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता) योजना के अंतर्गत कार्य कर रही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ समीक्षा बैठक में कही। इस बैठक का उद्देश्य भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के पुनर्वास, आजीविका से जोड़ने तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करना था। बैठक के दौरान विभिन्न एनजीओ ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों की विस्तृत प्रस्तुति दी। संस्थाओं ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर सैकड़ों लोगों से संपर्क किया, काउंसलिंग की और कई लोगों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालकर पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ाया। कई लाभार्थियों को शेल्टर होम में स्थान दिलाया गया तथा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए गए। प्रस्तुतियों में यह भी बताया गया कि लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड बनवाना, बैंक खाते खुलवाना, बीमा योजनाओं से जोड़ना, नगर निगम के माध्यम से वेंडर पंजीकरण कराना और राशन कार्ड के लिए आवेदन करना शामिल है। इसके साथ ही बच्चों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में दाखिला दिलाने तथा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं। मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि स्माइल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को समाप्त करना और बेसहारा लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार द्वारा एनजीओ को दिए जाने वाले संसाधनों और सहयोग के साथ पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी संस्थाएँ पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनजीओ को विश्वास के साथ जिम्मेदारी सौंपी है और यह अपेक्षा की जाती है कि वे जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा और सत्यापन किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण भी किया जा सकता है। रविंद्र इंद्राज ने कहा कि भिक्षावृत्ति केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि देश की छवि से भी जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि जब कोई विदेशी पर्यटक भारत आता है और सड़कों पर भिक्षावृत्ति के दृश्य देखता है तो इससे देश की छवि प्रभावित होती है। इसलिए इस समस्या का समाधान करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि समाज के इस वर्ग को भी सम्मानजनक जीवन और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। बैठक के दौरान कई संस्थाओं ने अपने सर्वेक्षण के आंकड़े प्रस्तुत किए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की पहचान, काउंसलिंग और पुनर्वास के उदाहरण शामिल थे। कुछ संस्थाओं ने लाभार्थियों की पहले और अब की स्थिति को प्रस्तुत करते हुए बताया कि किस प्रकार सरकारी सहयोग और सामाजिक प्रयासों के माध्यम से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इस अवसर पर पुनर्वासित बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी मंत्री को भेंट की गईं।

दिल्ली पुलिस अकादमी में विभिन्न कैडरों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

लोकतंत्र की शान

12 मार्च 2026 को Delhi Police के विभिन्न कैडरों के नवप्रशिक्षित पुलिसकर्मियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह Delhi Police Academy Jharoda Kalan में आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री Mohammad Ali थे, जिन्होंने सलामी ली। शपथ श्री Richhpal Singh द्वारा दिलाई गई। कुल 25 प्रशिक्षुओं ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिनमें 04 एएसआई (स्टेनो) (जिसमें 01 महिला शामिल), 01 महिला हेड कॉन्स्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर) तथा 20 आर/कांस्टेबल (वर्कशॉप हैंड) शामिल थे। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। एएसआई (स्टेनो) नीलम – कानून विषय में प्रथम तथा आउटडोर में प्रथम स्थान। एएसआई (स्टेनो) विनय फलवारिया – ऑल राउंड बेस्ट तथा कंप्यूटर एप्लिकेशन में प्रथम स्थान। एएसआई (स्टेनो) प्रमोद – शूटिंग में प्रथम स्थान। आर/कांस्टेबल (वर्कशॉप हैंड) ललित शर्मा – ऑल राउंड बेस्ट तथा इंडोर में प्रथम स्थान। आर/कांस्टेबल (वर्कशॉप हैंड) अजयपाल सिंह शेखावत – आउटडोर में प्रथम स्थान। सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद अली, उप निदेशक,

डीपीए द्वारा प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री मोहम्मद अली ने प्रशिक्षुओं को विभाग में सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया और इस बात पर जोर दिया कि बल का प्रत्येक सदस्य विश्वास, सुरक्षा और न्याय का प्रतीक बनकर कार्य करे।

राहुल गांधी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के यौन अपराधी एपस्टीन से संबंधों को लेकर संसद में सवाल उठाए

लोकतंत्र की शान, संवाददाता जीशान अली

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल से जुड़ा गंभीर संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की दोषपूर्ण विदेश नीति के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुई है और किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति यह तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदे। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया और पुरी की बेटी को जॉर्ज सोरोस से पैसा मिलने का खुलासा किया। उन्होंने कहा की पेट्रोलियम मंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि वे जेफरी एपस्टीन के मित्र थे। उन्होंने एक दस्तावेज का हवाला देते हुए यह भी कहा कि हरदीप

पुरी की बेटी को अरबपति जॉर्ज सोरोस से पैसा मिला है। इस दौरान राहुल गांधी के वक्तव्य पर सत्तापक्ष ने बौखलाहट में व्यवधान शुरू कर दिया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो यह शुरुआत है और मध्य-पूर्व युद्ध से भारत पर गंभीर असर पड़ने वाले हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति जिस प्रमुख समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ से होती है, वह बंद हो गया है। उन्होंने आगाह किया कि इसका भारत पर विशेष रूप से असर पड़ेगा क्योंकि देश में तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। उन्होंने मौजूदा स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि देश में कई जगह रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोगों में एलपीजी की कमी को लेकर घबराहट है। अभी भी थोड़ा समय है, मोदी सरकार को तुरंत इस संकट को दूर करने के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की, तो फिर करोड़ों भारतीयों का भारी नुकसान होगा।

भारत ने यूएन में कहा- हमने मानवाधिकारों के लिए किया डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल

लोकतंत्र की शान

जिनेवा। भारत ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में कहा कि हमने बड़े पैमाने पर सभी के अधिकारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया है। भारत ने नई तकनीक और डिजिटल टूल्स के सकारात्मक पहलुओं पर जोर देते हुए कहा कि इसने न्याय, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों, 1.4 अरब भारतीयों की डेमोक्रेटिक भागीदारी और हमारी महिलाओं के एम्पावरमेंट तक पहुंच को भी आसान बनाया है। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र के दौरान जारी आम बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह टिप्पणी की। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि जॉर्ज ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा हाल ही में दिए बयान को दोहराते हुए अपनी बात शुरू की, जिसमें डॉ. जयशंकर ने कहा था कि इस काउंसिल में हमारी बातचीत बयानों और प्रस्तावों से आगे बढ़कर सबसे कमज़ोर लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ठोस सुधार लाने पर होनी चाहिए। जार्ज ने कहा हाल ही में नई दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में यह माना गया कि एआई की ताकत का सबसे अच्छा एहसास तभी होता है, जब इसके फ़ायदे मानवता के बीच बराबरी से बांटे जाएं, जिसमें ग्लोबल साउथ की भागीदारी भी शामिल है। आतंकवाद ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बना हुआ है। हमें इसके सभी रूपों का मुकाबला करने के अपने इरादे पर अडिग रहना चाहिए। इस काउंसिल को इस मुद्दे पर एक आवाज़ में बोलते रहना चाहिए। इससे पहले सिबी जॉर्ज ने जिनेवा की अपनी इस यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) की महासचिव डोरेन बोगदान-मार्टिन के साथ एक बैठक की, जिसमें सुरक्षित और समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे तथा वैश्विक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव ने इसके अलावा साउथ सेंटर (विकासशील देशों का इंटरगवर्नमेंटल संगठन) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रो. कार्लोस कोर्रिया से मुलाकात की। उन्होंने साझा प्राथमिकताओं को

आगे बढ़ाने, समान ग्लोबल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विकासशील देशों के नजरिए ग्लोबल फैसले लेने को आकार दें। जॉर्ज ने जिनेवा में यूएन और दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में काम कर रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की और पिछले दस सालों में भारत में हुए शानदार सोशियो-इकोनॉमिक बदलाव पर रोशनी डाली।

दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महीने तक सभी प्रकार के प्रदर्शनों पर रोक लगाने के आदेश पर सवाल खड़ा किया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछा कि अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन पर पूरे तरीके से रोक लगाना जायज नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छात्रों के रवैये पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर सुनवाई केवल इसलिए कर रहे हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के अधिकारों का मामला है, लेकिन इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। छात्रों को अपने व्यवहार में सुधार लाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति क्यों आने दी गई। प्रॉक्टर एक अकादमिक व्यक्ति होता है। कोई अकादमिक व्यक्ति को ऐसा आदेश देने की नौबत क्यों आयी। दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के छात्र उदय भदौरिया ने दायर याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर की ओर से 17 फरवरी के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जिसमें सार्वजनिक सभाओं, जुलूस प्रदर्शन

या पांच व्यक्तियों के जुटने पर दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में रोक लगाई गई है। ये नोटिफिकेशन यूजीसी के इक्विटी गाइडलाइंस के आने के बाद विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के समूहों के बीच झड़पों की खबरें आने के बाद जारी किए गए। कोर्ट ने 25 फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के इस नोटिफिकेशन के बाद किरोड़ीमल कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज ने अपने परिसर में सख्त रुख अपनाते हुए आदेश का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अलावा निलंबन और निष्कासन की चेतावनी दी है। दोनों कॉलेजों ने अपने छात्रों और स्टाफ को इस संबंध में कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का ये नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। ये नोटिफिकेशन अकादमिक विमर्श को खत्म कर सकता है।

इराक ऑयल टैंकर अटैकः भारतीय दूतावास ने बचाई 15 भारतीयों की जान

लोकतंत्र की शान

बगदाद। इराक स्थित भारतीय दूतावास ने इराक के बसरा तट के पास एक तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्वक बचा लिया है। भारतीय दूतावास अपने नागरिकों व स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और बचाए गए भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। पश्चिम एशिया में ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस बीच मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले और कथित तौर पर अमेरिकी स्वामित्व वाले कच्चे तेल के टैंकर 'सेफसी विष्णु' पर इराक के बसरा के पास हमला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला ईरान की एक सुसाइड बोट द्वारा किया गया था। हालांकि इस दुर्भाग्यपूर्ण हमले में एक

भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई है। क्षेत्र में चल रहे तनाव के कारण इराक की राजधानी बगदाद स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी पहले से ही अलर्ट थे और इलाके में चल रही तमाम गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय दूतावास ने तुरंत बाकी 15 भारतीय सदस्यों को सुरक्षित स्थान (संभवतः बसरा के पास एक छोटे द्वीप) पर पहुंचा दिया है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा 11 मार्च, 2026 को मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाले

यूएस के क्रूड ऑयल टैंकर सेफसी विष्णु पर इराक के बसरा के पास हमला हुआ, जिसमें बदकिस्मती से एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई। बाकी 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। बगदाद में भारतीय दूतावास इराकी अधिकारियों और बचाए गए भारतीय नाविकों के साथ रेगुलर संपर्क में है और हर मुमकिन मदद दे रहा है। दूतावास मृतक क्रू मेंबर के परिवार वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है। वहीं दूसरी ओर शिपिंग महानिदेशालय (डीजीएस) ने एहतियात के तौर पर फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी को उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तौर पर भारतीय ध्वज वाले सभी जहाजों को चौबीसों घंटे निगरानी रखने, अपनी स्थिति की रिपोर्टिंग बढ़ाने और 'शिप सुरक्षा अलर्ट सिस्टम' का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा जीसीसी देशों में हमारे लगभग 1 करोड़ प्रवासी रहते हैं। हमारे प्रवासी समुदाय का कल्याण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्व रखता है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और इजरायल सहित क्षेत्र के कई नेताओं से बात की है। विदेश मंत्री भी इन देशों के साथ-साथ ईरान के समकक्षों के साथ नियमित संपर्क में हैं।

संक्षिप्त समाचार

कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधायक ने किया फीता काट कर शुभारंभ

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः गुरुवार को हसनपुर विधानसभा के ग्राम जेबड़ा मुस्तकम में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन वर्ष 2025–26 के अंतर्गत लगाए गए कृषि मेला एवं कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का लोकप्रिय विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने फीता काटकर शुभ आरम्भ किया, इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसामों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषक भाई अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस प्रशिक्षण का लाभ उठाएं वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर कार्य कर रही है इस मौके पर आदमपुर मंडल अध्यक्ष राजीव गोयल, प्रधान संघ अध्यक्ष यशपाल प्रधान, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हेमराज सैनी, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष ईश्वरचंद गुर्जर, डॉ राय प्रवेश वर्मा DDA कृषि विभाग, कपिल कुमार SMS कृषि विभाग, आज मुकेश चौहान ADO-AP कृषि विभाग, पवन चौहान कृषि विभाग, वीरेंद्र सिंह कृषि विभाग, ग्राम प्रधान इंद्रेश कुमार, बाहुल सिंह कृषि विभाग, हरपाल सिंह कृषक, रवि कुमार कषक, जगदीश सिंह कर्षक, हनीफ कर्षक, ओमपाल सिंह कर्षक, सुमित सिंह कृषक एवं आस-पास के ग्रामों से आए किसान व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे 1

हसनपुर में गैस गोदाम पर भारी भीड़ भाकियू बीआर अंबेडकर ने किया प्रदर्शन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुर : तहसील क्षेत्र में रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। गुरुवार की सुबह से ही भारी संख्या में गैस गोदाम के पास लोग खाली सिलेंडर लेकर एकत्र हो गए। इस दौरान उपभोक्ताओं की दूर तक लंबी लाइन लगी रही। इस अव्यवस्था के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन (बीआर अंबेडकर) ने मोर्चा खोला, यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी के नेतृत्व में पदाधिकारी गैस गोदाम पहुंचे और प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियां अपनी मर्जी से ऊंचे दामों पर गैस बेच रही हैं। जिसको लेकर यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटों के भीतर सभी पात्र उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से गैस उपलब्ध नहीं कराई गई, तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग गैस के लिए लंबी लाइनों में खड़े दिखे। इस मौके पर प्रमोद कुमार, अरविंद जाटव, सोनू गुर्जर, कुलदीप भारती, यासीन अली, नदीम, किरण पाल और रूम सिंह सहित दर्जनों किसान व यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को

लोक तंत्र की शान : लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा प्रदेश के 75 जनपदों के 1090 परीक्षा केन्द्रों में 14 मार्च एवं 15 मार्च को दो-दो पालियों में आयोजित कर रहा है। पूर्वान्ह में 10.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक एवं अपरान्ह 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत 4543 पदों पर अभ्यर्थियो से आवेदन आमंत्रित किए थे। इसमें कुल 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें पुरूष-11,66,386 हैं जबकि 4,09,374 अभ्यर्थी महिला हैं। लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु गुणवत्तापूर्ण परीक्षा केन्द्रों के चयन निर्धारण के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य/ केन्द्र के विद्यालय/ विश्वविद्यालय, पालीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आदि ही सम्मिलित किए गये हैं। महिला अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु उनके मण्डल का ही जनपद आवंटित किया गया है। लिखित प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, नकलविहीन एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के संबंध में इम्पर्सीनेशन कंट्रोल (प्रतिरूपण नियंत्रण) हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कई इंतजाम किए हैं। परीक्षा केन्द्रों की सीसीटीवी से मानीटरिंग हेतु त्रिस्तरीय कन्ट्रोल एवं कमांड सेंटर (परीक्षा केन्द्र, जनपद एवं बोर्ड) व्यवस्था की गई है।

रोजगार मेले में बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करने के निर्देश

लोक तंत्र की शान : बिजनौर। जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 17 मार्च को राजकीय आईटीआई परिसर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसको सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई बिजनौर को निर्देशित किया कि बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने जिला सेवायोजन अधिकारी को भी निर्देश दिए कि वे अपने स्तर से कंपनियों से संपर्क कर अधिक से अधिक युवाओं के रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को सेवायोजित करना है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने राजकीय और निजी आईटीआई के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि अपने-अपने संस्थानों से कोर्स पूरा करने वाले युवाओं को रोजगार मेले में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। बैठक में नगर निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रोजगार मेले के दौरान स्थल पर साफ-सफाई और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वच्छ पेयजल के लिए कैंपर आदि की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त पुलिस बल और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से रोजगार मेले के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, नोडल प्रधानाचार्य मंजुल मयंक, उपायुक्त उद्योग, जिला सेवायोजन अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

नजीबाबाद में बारात का सफर बना हादसा, दर्जनों बाराती घायल

लोकतंत्र की शान,(खिज़र अहमद)

नजीबाबाद : नजीबाबाद क्षेत्र में रायपुर रोड पर गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब बारात लेकर जा रही एक बस लकड़ी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। यह हादसा ग्राम किशनपुर आंवला के सामने उस समय हुआ, जब बस समीपुर से रायपुर की ओर बारात लेकर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में बड़ी संख्या में बाराती सवार थे। जैसे ही बस किशनपुर आंवला के पास पहुंची, सामने चल रही लकड़ियों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग सीटों से गिरकर घायल हो गए। हादसे में दर्जनों बाराती घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस और निजी वाहनों के माध्यम से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए रायपुर रोड पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू कराया

सीएम योगी ने श्रीराम मंदिर व हनुमानगढ़ी में किया दर्शन-पूजन

लोकतंत्र की शान

अयोध्या। गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले संकटमोचन हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन-पूजन किया और प्रदेश की सुख-शांति की कामना की। इसके बाद सीएम योगी ने श्रीराम मंदिर में श्रीरामलला के चरणों में शीश झुकाया। उन्होंने श्रीराम मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत संकटमोचन हनुमानगढ़ी मंदिर से की। उन्होंने यहां विधिवत पूजा-अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की। यहां से निकल कर मुख्यमंत्री श्रीराम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने श्रीरामलला के दर्शन किए, आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर परिसर में निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं से अवगत कराया।

प्रदेश में डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं, रसोई गैस की कमी के अफवाहों से बचें: मुख्यमंत्री

लोकतंत्र की शान

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रसोई गैस (एलपीजी) की निर्बाध और सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की घबराहट की स्थिति न बनने दी जाए तथा आमजन को समय-समय पर सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एलपीजी की वर्तमान मांग और आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी उत्पन्न न होने पाए तथा जिन उपभोक्ताओं ने एलपीजी की बुकिंग कराई है, उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध ढंग से सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को उनकी अगली रिफिल की संभावित तिथि के संबंध में भी समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, जितना कि अफवाहों के माध्यम से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। तेल कंपनियां प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एलपीजी की आपूर्ति और वितरण की वास्तविक स्थिति के बारे में आमजन को नियमित रूप से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है।

खुर्शीद मंसूरी ने किया आह्वान, 15 मार्च को बिजनौर पहुंचकर कार्यक्रम बनाएं ऐतिहासिक

लोकतंत्र की शान, (खिज़र अहमद)

नजीबाबाद : नजीबाबाद स्थित कैम्प कार्यालय पर आज़ाद समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 15 मार्च को बिजनौर में मान्यवर कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए साहनपुर नगर पंचायत के चेयरमैन एवं मुरादाबाद मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मान्यवर कांशीराम जी ने समाज के दबे-कुचले वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 15 मार्च को बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर उसे ऐतिहासिक और सफल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से संगठन को मजबूती मिलती है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भीम सेन हल्दिया, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष प्रशांत महासागर, नजीबाबाद विधानसभा अध्यक्ष अशोक कुमार, अयाज़ अंसारी, सुखबीर प्रधान, ओमवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, वाजिद मकरानी, साबू प्रधान, सभासद अच्छन राईन, शमशीद प्रधान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में पुलिस अलर्टः जुलूस, नारेबाजी और सड़क पर नमाज पर सख्त चेतावनी

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल। थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र की चौकी में आगामी ईद और जुम्मे की नमाज को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ संवाद कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बैठक में सीओ संभल कुलदीप कुमार ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस या प्रदर्शन निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीओ कुलदीप कुमार ने कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस मुद्दे को लेकर रील या भड़काऊ वीडियो बनाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने ईद और जुम्मे की नमाज से पहले क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान थाना प्रभारी सुधीर पवार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग त्योहारों के दौरान शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी समस्या की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बैठक में चौकी प्रभारी मोहम्मद शाह फैसल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित लोग मौजूद रहे, सिरसी चेयरमैन कौसर अब्बास, समाजसेवी व संभल मार्केटिंग के पूर्व चेयरमैन चौधरी सैयद मोहम्मद फैजान अली नक़वी, सभासद इनामुल हक, कयामुद्दीन, सैयद सलमान अब्बास उर्फ दानिश सिरसवी, सभासद साहिर किदवई, तनवीर,सभासद आशिक अब्बास, शिया जमा मस्जिद के मुतवल्ली चौधरी सैयद सीरत उरूज आलम, पूर्व चेयरमैन वसीम खान, फुरकान हैदर जैदी, ज़मा हैदर, हसन मेहंदी, और पप्पू समेत कई लोग उपस्थित रहे।

नगर पंचायत सिरसी की बजट बोर्ड बैठक स्थगित, अब 17 मार्च को होगी

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

सम्भल (सिरसी)। नगर पंचायत सिरसी में वित्तीय वर्ष 2026–27 के मूल बजट को लेकर प्रस्तावित बोर्ड बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। यह बैठक पहले 12 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे आयोजित की जानी थी। नगर पंचायत सिरसी के अध्यक्ष कौसर अब्बास द्वारा जारी सूचना के अनुसार अब मूल बजट से संबंधित बोर्ड बैठक 17 मार्च 2026 (मंगलवार) को प्रातः 10 बजे नगर पंचायत सिरसी कार्यालय के सभागार कक्ष में आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अपील की है कि निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित होकर बजट संबंधी कार्यवाही में भाग लें, जिससे नगर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

उधार दिए पैसे वापस मांगने पर युवक को गंभीर रूप से पीट कर किया घायल

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल
जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरुवार को क्षेत्र के एक युवक ने अपने उधर के पैसे मांगे तो आरोपी ने युवक को सरिया से पीटकर घायल कर दिया, बता ते चले कि मोहल्ला ईदगाह रोड निवासी सद्दाम पुत्र अबरार ने चामुंडा रोड निवासी एक युवक को कुछ रुपए कुछ समय पहले उधार दिए थे पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी युवक ने गाली गलौज शुरू कर दी विरोध करने पर आरोपी ने लोहे के शरीये से पीड़ित पर हमला कर दिया इस हमले में पीड़ित सद्दाम के सर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटे आई, घटना के बाद परिजन घायल सद्दाम को लेकर कोतवाली पहुंचे और पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने घायल को तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, कस्बा इंचार्ज राम प्रकाश ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर के आधार पर तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा 1

अलविदा जुमा पर समाजसेवी फैज़ान अली नक़वी का संदेश, इंसानियत और ईमानदारी से ही बनेगा बेहतर समाज

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

सम्भल/सिरसी माहे रमज़ान के मुकद्दस महीने का आख़िरी जुमा यानी अलविदा जुमा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा कर मुल्क में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। अलविदा जुमा का दिन मुसलमानों के लिए खास अहमियत रखता है, जो उन्हें रमज़ान की तालीमात—सब्र, तक़वा, इंसानियत और सच्चाई—की याद दिलाता है।‹इस अवसर पर समाजसेवी एवं मार्केटिंग सम्भल के पूर्व चेयरमैन चौधरी सैयद मोहम्मद फैज़ान अली नक़वी ने शहरवासियों को अलविदा जुमा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमज़ान का महीना इंसान को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और समाज में भलाई का पैगाम देने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की असली तालीम इंसानियत, सच्चाई और ईमानदारी में है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जरूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति अपने जीवन और कारोबार में ईमानदारी अपनाए और अपनी रोज़ी-रोटी हलाल तरीके से कमाए। जब इंसान अपनी कमाई को पाक और हलाल रखता है तो उसमें बरकत आती है और समाज में भी अच्छाई और भरोसे का माहौल बनता है। फैज़ान अली नक़वी ने कहा कि रमज़ान का महीना हमें गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की मदद करने का भी सबक देता है। ज़कात, सदका और खैरात के जरिए समाज में भाईचारे और बराबरी की भावना को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है और जो लोग समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, वे वास्तव में इस्लाम की असली तालीम पर अमल करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अहलेबैत (अ.स.) की सीरत पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हज़रत मौला अली (अ.स.) की जिंदगी हमें सच्चाई, इंसाफ और गरीबों की मदद का सबक देती है। अगर हम उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो समाज में अमन, भाईचारा और इंसाफ का माहौल कायम हो सकता है। अंत में उन्होंने शहर सम्भल और पूरे देश की खुशहाली के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह तआला हम सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और हमें इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और हलाल रोज़ी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि रमज़ान की तालीम को सिर्फ इस महीने तक सीमित न रखें, बल्कि पूरे साल अपनी जिंदगी में

संक्षिप्त समाचार

नौबतपुर में गैस सिलेंडर लेने के लिए उमड़ी भीड़, एजेंसी मालिक बोले - घबराकर पहुंच रहे लोग

पटना। पटना के नौबतपुर प्रखंड में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर ग्राहकों के बीच घबराहट का माहौल है। गुरुवार सुबह से ही गैस वितरण केंद्रों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई ग्राहकों को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस लेने के लिए सुबह से ही केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। मनीष कुमार, ललन कुमार, मुन्ना खान, असरेंद्र कुमार और रणधीर यादव जैसे ग्राहकों ने बताया कि उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, सर्वर की समस्या के कारण ओटीपी नहीं आने से वितरण प्रक्रिया धीमी हो रही है। हालांकि, गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है। आराध्य गैस एजेंसी के संचालक विवेक कुमार ने बताया कि अफवाहों के कारण लोग घबराकर एक साथ केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ रही है। भीड़ को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए नौबतपुर थाना में आवेदन भी दिया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विनोद कुमार राम ने पुष्टि की है कि क्षेत्र में गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अफवाहों की वजह से जरूरत से पहले ही गैस लेने केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने चार दिन पहले ही सिलेंडर लिया था, जबकि गैस लेने की निर्धारित अवधि 25 दिन की है। प्रशासन की ओर से नौबतपुर के सभी गैस केंद्रों पर जाकर लोगों को समझाया जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन का लक्ष्य है कि स्थिति को जल्द ही सामान्य किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

जदयू कार्यालय के बाहर बक्सर के कार्यकर्ताओं का धरना, बिना डेलीगेट वाले को जिला अध्यक्ष बनाने का आरोप

पटना। JDU के प्रदेश कार्यालय के बाहर गुरुवार को बक्सर जिले के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जमकर हंगामा किया। नाराज कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बक्सर जिला अध्यक्ष के चयन में संगठनात्मक नियमों की अनदेखी की गई है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस व्यक्ति को बक्सर जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उसके पास एक भी डेलीगेट नहीं है। इसके बावजूद उसे इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दे दी गई, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और पक्षपात किया गया। धरने पर बैठे अधिकांश कार्यकर्ता बक्सर के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सिंह यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि संगठन में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर मनमाने तरीके से निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की जाती है, लेकिन जिला अध्यक्ष के चयन में नियमों को नजरअंदाज किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व से मांग किया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि चयन प्रक्रिया में अनियमितता पाई जाती है तो इसे रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जाए। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पार्टी के कुछ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। हालांकि, नाराज़ कार्यकर्ता काफी देर तक प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना देकर अपना विरोध जताते रहे।

बिहार में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, बढ़ेगी उमस, 38-40°C तक जा सकता है तापमान

पटना। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला-बदला जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उमस भरी गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके कारण तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। कई जिलों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि 14 से 16 मार्च के बीच उत्तर और पूर्वी बिहार के कई इलाकों में आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में बीती रात तेज बारिश हुई, जिससे कुछ समय के लिए मौसम सुहावना हो गया। पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई जिलों में आसमान में बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। हालांकि, इन बादलों का असर ज्यादा नहीं दिख रहा है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में बादलों की वजह से तेज धूप से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन नमी अधिक होने के कारण उमस ने लोगों को काफी परेशान किया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय बिहार में पश्चिमी हवाओं के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भी वातावरण में मौजूद है। नमी और गर्मी के इस मिश्रण से बादल तो बन रहे हैं, लेकिन कोई मजबूत मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं होने के कारण भारी बारिश नहीं हो पा रही। इसी वजह से बादल होने के बावजूद मौसम शुष्क और उमस भरा बना हुआ है।

पांच अपराधी अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार, लूट की योजना बना रहे थे, पुलिस ने प्रिवेंटिव पुलिसिंग से पकड़ा

हाजीपुर। हाजीपुर नगर थाना पुलिस ने लूट की योजना बना रहे पांच अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी बूटन दास मठ स्थित आम के बगीचे से हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अवैध हथियारों के साथ लूट और डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए वैशाली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1, हाजीपुर सुबोध कुमार के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने किशन कुमार उर्फ बेदर्दी, विशाल कुमार, रवि कुमार, गोपी कुमार और मो. इमरान को मौके से गिरफ्तार किया। इनके पास से दो देशी कट्टे और दो जिंदा कारतूस सहित अन्य अवैध सामान बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वे आपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। वैशाली पुलिस ने 'प्रिवेंटिव पुलिसिंग' के तहत घटना को अंजाम देने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों ने नगर थाना क्षेत्र में लगभग 7-8 चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या-219/26 दर्ज किया गया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और पुलिस उनके आपराधिक इतिहास का पता लगा रही है। पुलिस की बरामद की गई सामानों में दो देसी कट्टे, दो जिंदा कारतूस, दो चाकू, दो पेचकस, एक लोहे का रुखानी, दो स्लाइड रिंच, तीन सिम कार्ड, 52,853 रुपए नगद, दो आईफोन, चार मोबाइल फोन, एक डिजिटल कैमरा, दो जोड़ी सोने जैसे कंगन, दो जोड़ी चांदी के बच्चे के बाला, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, एक ब्लूटूथ हेडफोन, एक छोटा चांदी का चम्मच, चार चांदी के बच्चे के बाला, दो जोड़ी चांदी के पायल और तीन जोड़ी चांदी की बिछिया शामिल हैं।

‘हर जिले में भू-माफिया की लिस्ट होगी रेडी’, 78 बालू घाटों की नीलामी के आदेश

सीमा पर सीसीटीवी निगरानी: विजय सिन्हा

एजेंसी, पटना

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग के 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर पीसी की। इस दौरान उन्होंने अवैध खनन, भूमाफिया और बालू माफिया के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई का संकेत दिया। उन्होंने कहा, नई सरकार नई पहल के साथ काम कर रही है। खनन विभाग को पारदर्शी और सख्त व्यवस्था की ओर ले जाया जा रहा है।

हर जिले में भूमाफिया की लिस्ट तैयार: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य के हर जिले में भूमाफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कई माफिया अवैध कमाई को जमीन में निवेश करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके पास भूमि राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी है, इसलिए भूमाफिया और जमीन माफियाओं की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पर्व-त्योहार में मिट्टी और बालू पर नहीं होगी रोक: इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्व-त्योहार के समय यदि कोई व्यक्ति पूजा या अन्य कार्यों के लिए मिट्टी या बालू ले जाता है तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बिना खनन विभाग के आदेश के सड़क पर पुलिस किसी वाहन को रोककर जांच नहीं करेगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर सड़क पर रोककर वसूली की शिकायतें सामने आई हैं, जिन्हें रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य: विजय सिन्हा ने कहा कि अन्य राज्यों से बिहार आने वाले खनिज से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य किया जाएगा। राज्य की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अवैध खनिज परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

78 बालू घाटों की नीलामी का आदेश: उन्होंने बताया कि राज्य में 78 बालू घाटों की नीलामी का आदेश जारी किया जा चुका है। कई घाटों को ठेकेदारों ने एक साल पूरा होने से पहले ही लौटा दिया है। कुछ लोगों ने अवैध उत्खनन के इरादे से ज्यादा बोली लगाई थी, लेकिन अब सख्ती के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, इसलिए घाट वापस कर रहे हैं। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों की राशि जब्त की जाएगी और उन्हें भविष्य के किसी भी टेंडर में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

जल्द शुरू होगा स्टोन चिप्स का खनन: डिप्टी सीएम ने बताया कि बिहार में जल्द ही स्टोन चिप्स का खनन शुरू किया जाएगा। फिलहाल राज्य में दूसरे राज्यों से स्टोन चिप्स मंगाए जाते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि इसका उत्पादन राज्य के भीतर ही हो। अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने 400 पुलिस बल की नियुक्ति की है। इसके अलावा सीमाओं और संवेदनशील इलाकों में निगरानी भी बढ़ाई जा रही है।

71 खनन योद्धाओं को किया सम्मानित: प्रेसवार्ता के दौरान विजय सिन्हा ने विभाग के 71 खनन योद्धाओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों और कर्मियों की सक्रियता के कारण ओवरलोडिंग और अवैध खनन में शामिल कई वाहनों को पकड़ा गया है। पिछले वर्ष खनन विभाग ने 3500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया था। इस वर्ष विभाग ने 3800 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है और उन्हें भरोसा है कि यह लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ बालू माफियाओं ने मिलकर विभाग को दबाव में लाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार किसी भी हालत में माफियाओं के आगे नहीं झुकेगी। बंद पड़े घाटों को फिर से चालू करने के लिए जल्द ही नया टेंडर निकाला जाएगा और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

सिलेंडर क्राइसिस, महावीर मंदिर में बचा 1 वीक का स्टॉक, मंदिर प्रबंधन बोला- भोज पर नहीं पड़ेगा कोई असर

पटना। पटना के महावीर मंदिर में हर दिन निःशुल्क दरिद्र नारायण भोज कराया जाता है। हालांकि, सिलेंडर क्राइसिस के कारण मंदिर प्रबंधन को भी परेशानी हो रही है। अभी कॉमर्शियल गैस की बुकिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मंदिर के पास बस एक हफ्ते का ही स्टॉक बचा है। मंदिर प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि महावीर मंदिर में आने वाले भक्तों को नवैद्यम प्रसाद और गरीबों को दरिद्र नारायण भोज अपने नियमित समय पर मिलता रहेगा। उसे हम प्रभावित नहीं होने देंगे। महावीर मंदिर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि हमारे पास कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का अभी एक हफ्ते का स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद हम लोग लकड़ी और कोयला पर शिफ्ट करेंगे, लेकिन भोजन बंद नहीं होगा। इसके अलावा जो नवैद्यम प्रसाद का निर्माण होता है उसमें भी कोई कटौती फिलहाल नहीं की जाएगी। हम लोग इलेक्ट्रिकल या किसी तरह के इंडक्शन की ओर स्विच करेंगे। दरिद्र नारायण भोज सुबह शाम दो टाइम चलता रहेगा, लोग यहां से भूखे पेट वापस नहीं जाएंगे।

रोहिणी बोलीं- प्रधानमंत्री जी, सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब होगा

एजेंसी, पटना

ईरान-इजराइल जंग के असर से बिहार में 3 दिन से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने की वजह से होटल, रेस्टॉरेंट पर काफी असर पड़ रहा है। घरेलू गैस को लेकर भी बिहार के कई जिलों में तीसरे दिन भी लोगों की लंबी कतार दिख रही है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर में एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए करीब 500 मीटर लंबी लाइन लगी है।

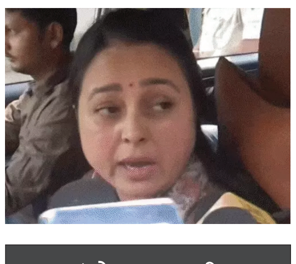

♦ कांग्रेस का सीएम को लेटर- चूल्हा-चौका संकट में है, कई शहरों में आज भी लंबी लाइन

एजेंसी खुलने का समय सुबह 9 बजे है, लेकिन उससे पहले ही गैस लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गोपालगंज, खगड़िया, औरंगाबाद, पटना समेत कई जिलों में लोग सुबह से ही गैस एजेंसी पहुंचने लगे।

इधर, लालू यादव की बेटी रोहिण आचार्य ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि, सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब मनेगा। नालंदा में पुलिस वाले जिप्सी पर सिलेंडर ले जाते दिखे।

वहीं, गैस की किल्लत को लेकर बिहार कांग्रेस ने सीएम नीतीश को लेटर लिखा है। प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने लिखा- 'यह समस्या सीधे बिहार के लोगों के पेट से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी, चूल्हा-चौका संकट में आ गया है।'

नाराज कांग्रेसियों का पटना में महासम्मेलन 17 मार्च को, कहा- स्लीपर सेल को उजागर करेंगे

एजेंसी, पटना

बिहार कांग्रेस में अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेसी पटना में 17 मार्च को महासम्मेलन करने वाले हैं। इस महासम्मेलन में पूरे राज्य से डेलिगेट्स और अधिकारी आएंगे। बोरिंग रोड के एक उत्सव हॉल में 17 मार्च को महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पूर्व AICC सदस्य आनंद माधव ने कहा इस महासम्मेलन के लिए 40 पॉलिटिकल जिलों का दौरा किया गया है और हमें उत्साहपूर्वक समर्थन मिला है। जिलों के कांग्रेसी ने हमारा पूरा साथ दिया है। इस महासम्मेलन के लिए पटना भी सजना शुरू हो जाएगा।

कांग्रेस की व्यवस्था और अराजकता से कार्यकर्ता ऊब चुके हैं: उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में बिहार कांग्रेस की व्यवस्था और अराजकता से कार्यकर्ता ऊब चुके हैं। सब के सब बदलाव और एजेंट से मुक्ति चाहते हैं। सत्ता के दलाल ने कांग्रेस को गर्त में ला दिया है। जब सदन में कांग्रेस के चार विधायक थे, तब भी कांग्रेस इतनी लाचार नहीं महसूस कर रही थी जितनी की अब है। हम समर्पित कांग्रेसी एक कोशिश कर रहे हैं, कि बिहार में कांग्रेस जिंदा हो। वे लोग बिहार को कांग्रेस मुक्त करने का सुपारी लेकर आए हैं।

राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता बिहार से होकर निकलता है: बिहार कांग्रेस की हार का कारण टिकट में धांधली के साथ-साथ ऐसे लोगों को नजर अंदाज करना है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को जीवित रखें। हमारा लक्ष्य 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता बिहार से होकर निकलता है। वहीं, संगठन सृजन के नाम पर लूट मचाया जा रहा है। पहले

❒ राहुल गांधी के पीएम बनाने का रास्ता बिहार से होकर गुजरता

कांग्रेस में जुड़ने के लिए 5 रुपए होते थे। उसे बढ़ाकर 10 रुपए किया गया, लेकिन अब 50 रुपए लिए जा रहे हैं।

इस सम्मेलन में कांग्रेस के स्लीपर सेल को उजागर करेंगे: पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने कहा कि हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से राहुल गांधी की पार्टी में स्लीपर सेल को उजागर करेंगे। इस महासम्मेलन के बाद हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और वहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। चुनाव के बाद कांग्रेसी काफी निराश हुए हैं। राजेश राम की वजह से हम लोगों को यह सम्मेलन और जिला का दौरा करना पड़ा है। जब जब कांग्रेसियों पर अत्याचार होगा, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। जिलों में कांग्रेसियों ने खुद हमसे आकर संपर्क किया और वर्तमान में बिहार कांग्रेस में चल रही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के खिलाफ इस महासम्मेलन में शामिल होने की इच्छा जताई है।

रेड पड़ते ही खिड़की से फेंके नोटों के बंडल अधिकारियों ने कचरे से निकाले 5 लाख

एजेंसी, पटना

पटना में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पंकज कुमार के 3 ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई (SVU) की रेड चल रही है। टीम जैसे ही पंकज कुमार के घर में दाखिल हुई वो खिड़की से नोटों के बंडल फेंकने लगे। टीम ने कचरे के ढेर से 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। अब तक की कार्रवाई में 15 लाख कैश जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेड जारी है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पंकज कुमार मूल रूप से मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके के रहने वाले हैं। वो बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMSICL) के DGM (प्रोजेक्ट) हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में गुरुवार को उनके 2 घरों और ऑफिस पर छापेमारी की गई है। SVU टीम ने अहले सुबह लगभग 8 बजे पटना के कदमकुंआ इलाके स्थित कनिका मैहर अपार्टमेंट में छापेमारी की। उस वक्त DGM पंकज कुमार अपने पूरे परिवार के साथ घर पर मौजूद थे। इस दौरान लगभग 96 लाख से अधिक अवैध संपत्ति, जिसनें कैश, गहने, जमीन से संबंधित दस्तावेज और कुछ आर्नामेंट्स बरामद किया गया है। फिलहाल, SVU टीम की जांच जारी है।

96 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति बनाने के आरोप: SVU ने पंकज कुमार के खिलाफ कांड संख्या-10/2026 दर्ज किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, पंकज कुमार ने अपनी लगभग 11 सालों की सर्विस के दौरान दौरान अलग-अलग पदों पर रहते हुए अवैध रूप से भारी संपत्ति अर्जित की। निगरानी इकाई का आरोप है कि एक लोक सेवक होने के बावजूद उन्होंने भ्रष्टाचार से लगभग 96 लाख 46 हजार 666 रुपए की ऐसी संपत्ति बनाई, जो उनके ज्ञात और वैध आय के स्रोतों से कहीं अधिक है।

BMSCIL दफ्तर में SVU टीम कर रही छानबीन: विशेष निगरानी इकाई की 5 सदस्यीय टीम BMSCIL के दफ्तर पहुंच जांच कर रही हैं। SVU की इस टीम को डीएसपी राजकुमार लीड कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 1 घंटे से छापेमारी के दौरान कागजातों को खंगाल रही हैं। इसके अलावा पटना के पीएमसीएच के BMSCIL कार्यालय में भी विशेष निगरानी की एक टीम छानबीन कर रही है।

❒ पटना में स्वास्थ्य अधिकारी के घर से 15 लाख मिले

SVU टीम की जांच जारी: इस मामले में विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना द्वारा तलाशी वारंट जारी किया गया था। इसी के आधार पर गुरुवार को छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। निगरानी टीम अभी दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य अहम साक्ष्यों की गहन जांच कर रही है। छापेमारी दल का नेतृत्व कर रहे विशेष निगरानी इकाई के डीएसपी संजय वर्मा ने बताया कि, 'डीजीएम पंकज कुमार के तीन ठिकानों पर छापेमारी जारी हैं।'

सहायक अभियंता के पद पर मिली थी नियुक्ति: पंकज कुमार को सहायक अभियंता (Assistant Engineer) के रूप में नियुक्ति मिली थी। लगभग 11 वर्षों तक वह विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, पटना तथा अन्य स्थानों पर पंकज कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कई भूमि/फ्लैट तथा अन्य संपत्तियाँ हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1,39,00,000/- है, जो भ्रष्ट और अवैध तरीकों से अर्जित की गई हैं।

दानापुर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियार-कारतूस और 10 लीटर देसी शराब बरामद

एजेंसी, पटना

दानापुर की शाहपुर पुलिस ने दियारा क्षेत्र से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और 10 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। दानापुर एएसपी शिवम धाकड़ ने यह जानकारी दी।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान पतलापुर फूटानी बाजार निवासी आशीष कुमार और सारण जिले के सोनपुर निवासी विनोद महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने आशीष के पास से एक देशी कट्टा और विनोद के पास से दो जिंदा कारतूस बरामद किए।

मकई के खेत में दो युवक पकड़ाए: एएसपी धाकड़ ने बताया कि 11 मार्च की शाम करीब 8 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, पतलापुर के एक मकई के खेत में दो युवक अवैध हथियारों के साथ शराब बेच रहे थे।

सूचना के सत्यापन के बाद मकसूदपुर टीओपी और शाहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम

❒ आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस

जब मौके पर पहुंची तो दोनों युवक भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। मकई के खेत से 15 लीटर के प्लास्टिक के डिब्बे से लगभग 10 लीटर अवैध देशी शराब भी बरामद की गई।

पुलिस आपराधिक इतिहास खंगाल रही: शाहपुर थाना में कांड संख्या 91/26 दर्ज किया गया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि दोनों तस्कर कब से इस धंधे में शामिल थे और उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल, दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

किसानों के लिए 100 प्लस स्टॉल लगे, किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र

एग्रो बिहार-2026

एजेंसी, पटना

पटना के गांधी मैदान में आज से चार दिवसीय एग्रो बिहार-2026 राज्यस्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला शुरू हो गया। 12 से 15 मार्च तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। कृषि मंत्री ने कहा, यह आयोजन किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत मशीनों और नई खेती पद्धतियों से परिचित कराने का बड़ा मंच बनेगा। इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

3.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में लगा विशाल मेला: कृषि मंत्री ने बताया कि लगभग 3.25 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में आयोजित इस मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर देश-भर की कंपनियां और संस्थान आधुनिक कृषि यंत्रों, उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मेले में बिहार के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि यंत्र निर्माता भी हिस्सा ले रहे हैं। यहां किसान ट्रैक्टर से जुड़े उपकरण, उन्नत बीज बोने की मशीन, हैप्पी सीडर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, स्प्रे मशीन और कृषि ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों को नजदीक से देख सकेंगे।

91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान: मेले में किसानों को सरकार की कृषि यांत्रिकरण योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 91 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस साल से अनुदान की राशि सीधे लाभुक किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। किसान यंत्रवार अनुदान की जानकारी विभागीय वेबसाइट, बिहार कृषि मोबाइल एप, जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कृषि कार्यालय या कृषि समन्वयक से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए अधिक अनुदान का विशेष प्रावधान किया है। वहीं 20 हजार रुपये या उससे कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर निबंधित गैर-रैयत किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

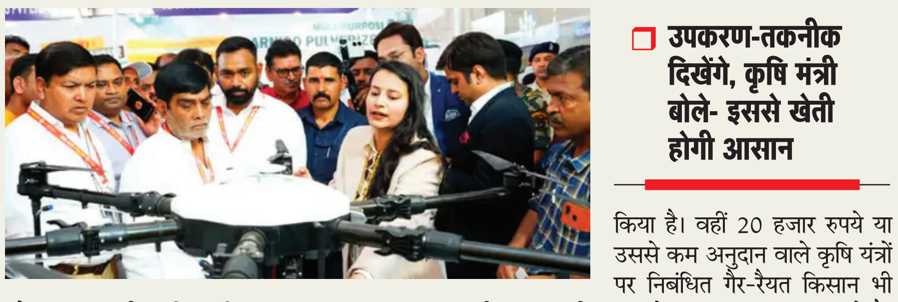

❒ उपकरण-तकनीक दिखेंगे, कृषि मंत्री बोले- इससे खेती होगी आसान

किसान पाठशाला में दी जाएगी आधुनिक खेती की जानकारी: मेले में विशेष रूप से किसान पाठशाला का आयोजन किया गया है, जहां कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ किसानों को नई तकनीकों, आधुनिक यंत्रों के उपयोग और बेहतर खेती पद्धति की जानकारी देंगे। इसके अलावा राज्य के सभी कृषि महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी इस मेले का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि उन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों और तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान मिल सके।

विभागों की योजनाओं की भी दी जा रही जानकारी: इस मेले में केवल कृषि यंत्र ही नहीं बल्कि कई विभाग भी अपने स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। इनमें खाद्य प्रसंस्करण, पशु एवं मत्स्य संसाधन, गन्ना उद्योग, उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग तथा कॉम्फेड शामिल हैं। किसानों को इन विभागों की योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सहायता से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

फरीदाबाद : टेलीग्राम टास्क में निवेश के नाम पर ठगी, खाताधारक गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : फरीदाबाद। टेलीग्राम टास्क में निवेश के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के एक मामले में साइबर थाना बल्लभगढ की टीम ने खाताधारक को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में बल्लभगढ निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना बल्लभगढ में शिकायत दी थी। उसने शिकायत में बताया कि 20 दिसंबर 2025 को उसके टेलीग्राम पर ओबराय टीलेटी प्रोजेक्ट के नाम से एक लिंक आया। लिंक पर क्लिक करते ही वह एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड गया। फिर शिकायतकर्ता ने टेलीग्राम टास्क में निवेश के नाम पर ठगों द्वारा बताये खाता में विभिन्न ट्रांजेक्सन के जरिये कुल आठ लाख आठ हजार रुपये निवेश किये। इसके बाद उसे कोई पैसा वापस नही मिला। इस शिकायत पर साइबर थाना बल्लभगढ में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब निवासी लखवीर (22) को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि लखवीर खाता प्रोवाइडर व ऑपरेटर है। आरोपी आठवीं पास है। खाता में ठगी के चार लाख रुपये आये थे। आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।

कैथल : खुराना के पास पेड़ से टकराई बाइक भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की मौत

लोकतंत्र की शान : कैथल। जिले के गांव खुराना के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव दयोरा से खुराना की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन चोटें ज्यादा होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को देख रहे राहगीरों ने तुरंत सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले खुशीराम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खुशीराम गांव दयोरा में स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था और रोजाना की तरह अपने काम से आ रहा था। हादसे की खबर मिलते ही उसके परिवार और साथ काम करने वाले मजदूरों में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और दो बेटियां शामिल हैं। सदर थाना के एसएचओ रमेश चंद्र ने गुरुवार को बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान हाईकोर्ट : हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक, हत्या के आरोपित को दी जमानत

लोकतंत्र की शान : जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या से जुडे महत्वपूर्ण मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आरोपित की सजा को निलंबित कर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस फरजंद अली व जस्टिस संदीप शाह की डबल बेंच ने .न्यायेतर स्वीकारोक्ति व गवाहों क़े अदालत में दिए गए बयान और उनके पक्षद्रोही होने व रिकॉर्ड में पाए गए विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया । सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किये गए गवाहों ने पक्षद्रोही बयान दिए, अभियोजन द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार भी मेडिकल व एफएसएल रिपोर्ट क़े मुताबिक मुल्जिम को जुर्म से नहीं जोड़ता पाया। श्री डूंगरगढ़ क़े जिला न्यायाधीश की अदालत ने 6 अक्टूबर 2025 को आरोपित को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपित ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा निलंबन की मांग की थी। अपीलार्थी की तरफ से पक्ष रखते हुए एडवोकेट जे पी छाँगाणी , विमल छाँगाणी ने कोर्ट का ध्यान जिला न्यायालय द्वारा दिए निर्णय में न्यायेतर स्वीकारोक्ति को मुख्य आधार बनाया।

पति ने पत्नी और आठ साल की बेटी की तलवार से हत्या की, खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर

लोकतंत्र की शान : जयपुर। जयपुर जिले के मौजमाबाद क्षेत्र में बीती देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और आठ वर्षीय बेटी की तलवार से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के अनुसार यह घटना मोखमपुरा थाना इलाके के बिचून गांव में बुधवार रात हुई। आरोपी खुशजीत पुत्र रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी सरोज देवी (35) और बेटी वंशिका (8) पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुशजीत मोखमपुरा थाने पहुंच गया और पुलिसकर्मियों से कहा कि उसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर दूदू उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामले की जांच के लिए मौजमाबाद तहसील के एसडीएम बलवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और डीएसपी दीपक खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण आर्थिक तंगी माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरणों के माध्यम से देंगे तीरंदाजी का प्रशिक्षण

लोकतंत्र की शान : बीकानेर। एकलव्य तीरंदाजी अकादमी में नए सत्र की शुरुआत के साथ इस बार प्रशिक्षण को और अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक बनाया जाएगा। अकादमी के अध्यक्ष एवं तीरंदाजी प्रशिक्षक अनिल जोशी ने बताया कि इस वर्ष खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उपकरणों के माध्यम से तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों की तकनीक और प्रदर्शन में सुधार हो सके। उन्होंने बताया कि आधुनिक खेलों में केवल तकनीकी अभ्यास ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स साइंस की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अकादमी में खिलाड़ियों के लिए नियमित रूप से स्टूडेंट साइकोलॉजी, फिजियोथैरेपी और फिटनेस सेशन भी आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों के माध्यम से खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती, शारीरिक फिटनेस और प्रतियोगिताओं के दबाव को संभालने की बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। जोशी ने बताया कि अकादमी का नया सत्र 23 मार्च से प्रारंभ किया जा रहा है। नए सत्र में इंडियन रिकर्व और कंपाउंड कैटेगरी के लिए नए खिलाड़ियों से आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अकादमी का उद्देश्य बीकानेर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करना है।

सच्चाई उजागर होने के बाद भी कार्यवाही ठंडे बस्ते में

तीसरी संतान पैदा करने वाले अपात्र शिक्षक भी दे रहे सेवा

लोकतंत्र की शान

सीधी। एक तरफ जहां कई विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा जनसंख्या नीत 2000 एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 10 मार्च 2000 को संशोधन किए गए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(9) के शर्तों का उल्लंघन करने पर सेवा समाप्त कर दी गई है।वहीं जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत कई शिक्षक उपरोक्त शर्तों को उल्लंघन कर 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान पैदा कर चुके हैं जिसको लेकर एक पखवाड़े पूर्व कई समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की गई थी बावजूद इसके जांच कार्यवाही ठंडे बस्ते में पड़ी है और सेवा से अपात्र होने पर भी ऐसे शिक्षक सेवा में बने हुए हैं।जिस कारण जिला शिक्षा अधिकारी की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में मानी जा रही है।क्योंकि ऐसे मामलों को स्वतःसंज्ञान लेकर कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना चाहिए लेकिन जब समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई और मामला सार्वजनिक हो गया फिर भी जांच कार्यवाही में हीला हवाली करने पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विकासखंड मझौली अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों के संबंध में उस समय जानकारी मंगाई गई थी जब मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में तत्कालीन विधायक संजय शाह मकड़ाई द्वारा 10 दिसंबर 2019 को अतारांकित प्रश्न क्रमांक 559 के तहत सामान्य प्रशासन मंत्री के समक्ष सवाल उठाया था कि जिन शासकीय सेवकों ने जीवित तीन संतानों में तीसरे बच्चे की जानकारी छुपा रखी है वह जानकारी ऐसे शासकीय सेवक की जानकारी प्राप्त कर उनको सेवा से कब तक अपात्र कर दिया जाएगा तथा ऐसे शासकीय सेवकों की कुल संख्या बताएं? इस प्रश्न के बाद पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक विभाग से जानकारी एकत्रित की गई थी उसी के तहत विकासखंड मझौली से भी जानकारी एकत्रित की गई थी लेकिन फिर उसे मामले में लंबी सौदेबाजी के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उदाहरण के तौर पर दिनेश कुमार गुप्ता प्राथमिक शिक्षक यूनिक आईडी BC 2283 नियुक्ति दिनांक 01.07.1997 एवं तीसरे बच्चे का जन्म 07. 10. 2011 संस्था यू ई जी एस हरिजन बस्ती बोदारी जिसे उन्नयन कर वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला हरिजन बस्ती बोदारी किया गया है।

इन पर हो चुकी है कार्यवाही

26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संस्थान पैदा करने के आरोप में जिला छिंदवाड़ा के विकासखंड हर्रई के कन्या प्राथमिक शाला हर्रई में पदस्थ सहायक अध्यापक पुरुषोत्तम डेहरिया की सेवा समाप्त की जा चुकी है।इसी तरह कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना के पत्र क्रमांक 423 आदेश दिनांक 6 मार्च 2025 के तहत प्राथमिक शिक्षक नसीर खान वर्तमान पदस्थापना शासकीय प्राथमिक शाला करइया संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नादन विकासखंड मैहर की तीसरी संतान पैदा करने के कारण सेवा समाप्त कर दी गई है।

इनका कहना हैं। मामले को लेकर खबर प्रकाशन के बाद संज्ञान लिया गया है और जांच के लिए कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। मैं अभी रीवा में हूं कल ऑफिस में आकर दिखवाता हूं। पवन कुमार सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी।

पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर निगम के 14 कर्मचारियों को चेतावनी पत्र, एक को कारण बताओ नोटिस

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

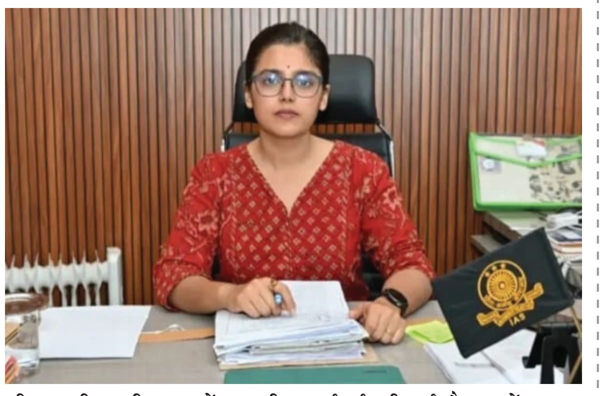

कटनी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति निकट आते ही शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बकाया राजस्व वसूली सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। निगमायुक्त तपस्या परिहार द्वारा राजस्व वसूली कार्य की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई की गई है।निगमायुक्त द्वारा हाल ही में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में वसूली कार्य में लापरवाही पाए जाने पर 14 कर्मचारियों को चेतावनी पत्र जारी किया गया है, जबकि एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई जिन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनमें बाजार शाखा के सहायक ग्रेड तथा सहायक राजस्व निरीक्षक एवं वसूलीकर्ता शामिल हैं। इनमें वार्ड क्रमांक 32, 43, 31, 33, 40, 41, 4, 8, 24, 39, 3, 12, 18, 42, 29 एवं 30 से संबंधित कर्मचारी शामिल हैं।

डॉ. रिकेश शर्मा को सिहावल बीएमओ की कमान

रिश्वत लेते पकड़े गए थे पूर्व बीएमओ, रिक्त था पद

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के स्वास्थ्य महकमे में सिहावल के मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी पद को लेकर जारी असमंजस के बीच आखिरकार नया आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बुविता खरे ने आदेश जारी करते हुए जिला चिकित्सालय सीधी में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रिकेश शर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल का मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार उनके वर्तमान पद के साथ आगामी आदेश तक सौंपा गया है। जारी आदेश अनुसार प्रशासनिक कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भोपाल से कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा भी व्यक्त की गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दरअसल सीधी जिले के सिहावल बीएमओ का पद पिछले कुछ समय से विवाद और असमंजस में बना हुआ था। इससे पहले इस पद के लिए डॉ. राम भूषण पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह पद ग्रहण नहीं किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. कपिल कुमार सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने भी यह पद स्वीकार नहीं किया। अब लगातार दो डॉक्टरों द्वारा जिम्मेदारी लेने से इनकार के बाद स्वास्थ्य विभाग को नया निर्णय लेना पड़ा। इसी क्रम में अब जिला

चिकित्सालय सीधी में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. रिकेश शर्मा को सिहावल बीएमओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी आदेश प्रभावहीन होने के बाद डॉ. कपिल कुमार सिंह अपनी मूल पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपुर में पूर्ववत पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

पेट्रोलियम पदार्थो और नेचुरल गैस का पर्याप्त भण्डार है मौजूद - मुख्य सचिव

» कलेक्टर गैस के वितरण तथा भण्डारण पर कड़ी निगरानी रखें - मुख्य सचिव

लोकतंत्र की शान

सीधी। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों तथा एलपीजी की आपूर्ति एवं वितरण की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि खाड़ी देशों में अशांति के कारण कच्चे तेल तथा गैस की आपूर्ति में असर पड़ा है, लेकिन देश में और प्रदेश में कहीं भी पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कमी नहीं है। इनके पर्याप्त भण्डार मौजूद हैं। कलेक्टर एलपीजी के वितरण और भण्डारण पर कड़ी निगरानी रखें। यदि कोई व्यक्ति इनका अवैध कारोबार अथवा कालाबाजारी करता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। गैस सिलेण्डर रिफिल कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग तथा वितरण की व्यवस्था कराएं। आयल कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। गैस तथा पेट्रोलियम पदार्थों के वितरण के संबंध में भ्रामक और तथ्यहीन समाचारों तथा सूचनाओं का तत्काल खण्डन कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर सूचनाओं का समन्वय से आदान-प्रदान करें। सीएम हेल्पलाइन में गैस संबंधी शिकायत मिलने पर उसे तत्काल संबंधित आयल कंपनी को भेजकर 24 घंटे में शिकायत का निराकरण कराएं। कॉमन सर्विस सेंटर तथा अन्य प्लेटफार्मों से भी गैस बुकिंग की सुविधा शुरू कराएं। आयल कंपनियाँ अपने सर्वर की क्षमता में वृद्धि कराएं जिससे ऑनलाइन बुकिंग में उपभोक्ताओं को किसी तरह की कठिनाई न हो। होटल संचालकों, बारात घर संचालकों तथा कामर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ बैठक कर उन्हें वैकल्पिक साधनों के उपयोग के लिए प्रेरित करें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी गैस की आपूर्ति के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

परमिट पर बंद 11 केवी लाइन में उतरा करंट

लाइन में काम कर रहे दो मैकेनिक झुलसे, एक की हालत गंभीर

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के बहरी क्षेत्र स्थित डीसी कुबरा में बिजली विभाग के दो कर्मचारी कार्य के दौरान करंट की चपेट में आकर झुलस गए। बताया गया है कि ये मैकेनिक 11 केवी विद्युत लाइन पर काम कर रहे थे, जिसे परमिट पर बंद किया गया था। घायलों में एक की हालत गंभीर है जिसे गंभीर हालत में रीवा रेफर किया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी अनुसार डीसी कुबरा क्षेत्र में बिजली विभाग 11 केवी लाइन पर उपकरण लगाने और नई लाइन खींचने का काम चल रहा था। विभागीय प्रक्रिया के तहत इस लाइन को परमिट पर बंद किया गया था और कर्मचारी उसी के आधार पर पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे। सुबह कार्य के दौरान अचानक लाइन में विद्युत प्रवाह चालू हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने लाइन में बिजली आपूर्ति चालू कर दी, जिससे पोल पर काम कर रहे दोनों मैकेनिक करंट की चपेट में आ गए, करंट लगने से दोनों कर्मचारी झुलस गए। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कराई और घायलों को पोल से नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया।

इंदिरा नगर man चौराहे पर जमीन पर अवैध कब जा खुले आम किया जा रहा है

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 1 में इंदिरा नगर मेन चौराहे पर जमीन पर अवैध कब जा खुले आम किया जा रहा है जबकि इस जमीन पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत सुलभ शौचालय बनाया जा सकता है पर नगर निगम की अतिक्रमण विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से जमीन पर जो की शासकीय की है खुलेआम का निर्माण किया जा रहा है कृपया कलेक्टर महोदय एवं नगर निगम के उच्च अधिकारी महोदय संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्य को रुकवाएं एवं कानूनी कार्रवाई तत्काल करें बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 1 में इंदिरा नगर man चौराहे पर शासकीय जमीन पर अवैध कब जा खुले आम किया जा रहा है जबकि इस जमीन पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत सुलभ शौचालय बनाया जा सकता है पर नगर निगम की अतिक्रमण विभाग के कुछ कर्मचारियों की

मिली भगत से जमीन पर जो की शासकीय की है खुलेआम का निर्माण किया जा रहा है कृपया कलेक्टर महोदय एवं नगर निगम के उच्च अधिकारी महोदय संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्य को रुकवाएं एवं कानूनी कार्रवाई तत्काल करें

गुरुग्रामः युवक की अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला समेत तीन गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

गुरुग्राम। एक युवक की साजिश के तहत अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपये ऐंठने की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने गुरुवार को बताया कि आरोपियों के कब्जा से एक लाख 63 हजार रुपये, एक स्कॉर्पियो गाड़ी व चार मोबाइल बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार छह मार्च को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-37 गुरुग्राम में एक शिकायत दी। उसने बताया कि वह सेक्टर-83 स्थित एक लैब में काम करता है। गत 25 फरवरी को वह एवीएल सोसायटी मोहम्मपुर में ज्योति नामक महिला का ब्लड सेंपल लेने गया था। उस महिला ने ब्लड रिपोर्ट के लिए उसके मोबाइल नंबर ले लिए थे। इसके बाद इन दोनों की आपस में बात होने लगी। वह महिला उससे मिलने की कहने लगी। इसके बाद दो मार्च को वह फिर से उस महिला का ब्लड सेंपल लेने गया। उस महिला के फ्लैट में जाने के कुछ समय बाद उस महिला ने फ्लैट का दरवाजा खोलकर छोड़ दिया, तभी वहां पर दो व्यक्ति आए तथा उसके साथ मारपीट करते हुए उसके कपड़े उतारकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली। उसको ब्लैकमेल करके उससे रुपये ट्रांसफर करवा लिए। साथ ही झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगे। इसके बाद वे उसको स्कॉर्पियो गाड़ी में लेकर गए। झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर रुपये ट्रांसफर करवाए। पांच लाख रुपये और देने की कहने लगे। उस दिन के बाद से वे व्यक्ति फोन करके लगातार उस पर रुपए का दबाव बना रहे थे। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-37 में केस दर्ज करके जांच शुरू की गई। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के जिला अलवर निवासी हरीश यादव, जिला महेंद्रगढ़ निवासी श्याम सुंदर को सती चौक गुरुग्राम से तथा आरोपी महिला ज्योति निवासी ताजनगर गुरुग्राम को गुरुग्राम से ही गिरफ्तार किया। आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि तीनों आरोपियों की जान-पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। इसके बाद इन्होंने पैसे कमाने के लिए एक साजिश के तहत योजना बनाई और इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के कब्जा से एक लाख 63 हजार रुपये, वारदात में प्रयोग की गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी व चार मोबाइल फोन बरामद किए गए।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में भी कुकिंग गैस संकट का असर, आज से लोगों को आधा सिलेंडर ही मिलेगा

काठमांडू। नेपाल में पिछले दो महीनों से बाजार में गैस की कमी देखी जा रही है। साथ ही पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण भी लोग गैस जमा करके रखने लगे हैं, जिससे संकट और बढ़ गया है। इसलिए आयल निगम ने अब उपभोक्ताओं को खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर आधा ही उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। निगम के कार्यकारी निदेशक चंद्रिका भट्ट ने बताया कि गुरुवार को हुई निगम की संचालक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आम जनता की आवश्यकता से अधिक गैस सिलेंडर जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण बाजार में आधा गैस सिलेंडर ही भेजने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि निगम फिलहाल इंडियन आयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) से गैस खरीदकर नेपाल में बिक्री करता है, लेकिन हाल के दिनों में भारत से मांग के अनुसार गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नेपाल में औसतन प्रतिदिन लगभग 120 गैस बुलेट (टैंकर) की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में करीब 80 बुलेट के आसपास ही आपूर्ति हो रही है।

जहाज पर हमले के बाद तीन थाई क्रू लापता, बैंकॉक ने ईरान से मांगी सफाई

इस्तांबुल। अमेरिका-इजराइल और के ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर बुधवार को हुए हमले के संदर्भ में थाईलैंड ने ईरान से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। घटना के समय जहाज पर कुल 23 लोग सवार थे जिसमें से चालक दल के तीन सदस्य लापता हैं, जबकि अन्य लोगों को बचा लिया गया था। वहीं इस घटना से पूर्वी एशिया के समुद्री क्षेत्रों में हालात बेहद संवेदनशील बन गए हैं। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू ने बताया कि बैंकॉक ने गुरुवार को ईरान से स्पष्टीकरण मांगी और बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में थाई झंडे वाले जहाज पर हुए हमले के बाद विरोध दर्ज कराया, जिसमें चालक दल के कम से कम तीन सदस्य लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के चालक दल के 23 सदस्यों वाली मयूरी नारी जहाज पर हमला तब हुआ जब यह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी से भारत की ओर जा रहा था। इसी दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले चल रहे थे और तेहरान इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था। अनाडोलू एजेंसी ने थाई मीडिया के हवाले से बताया कि थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को लेकर बैंकॉक में ईरान के राजदूत नासेरदीन हैदरी को तलब करके मामले में स्पष्टीकरण मांगा। दूसरी ओर थाई विदेश मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव संकट और दुनिया भर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। यह संकट इस क्षेत्र और उससे बाहर के देशों में बेगुनाह नागरिकों की जान और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हमले के बाद ओमान की नौसेना ने चालक दल के 20 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया था।

मानव तस्करी के जाल में फंसे 16 नेपाली नागरिकों को कंबोडिया से वापस लाया गया

काठमांडू। मानव तस्करों के झांसे में आकर कंबोडिया में फंसे 16 नेपाली नागरिकों को गुरुवार को स्वदेश वापस लाया गया। इसमें बैंकाक स्थित नेपाली राजदूतावास, कंबोडिया सरकार और गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का समन्वय रहा। दूतावास के अनुसार इन लोगों को विभिन्न माध्यमों से कंबोडिया पहुंचाकर अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन स्कैमिंग (ठगी) केंद्रों और कैसिनो में गैरकानूनी काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा उनमें से कुछ लोग बिना वीजा के ही वहां रह रहे थे। दूतावास ने बताया कि अभी भी वहां कठिन परिस्थितियों में फंसे अन्य नेपाली नागरिकों के उद्धार के लिए प्रयास जारी हैं।

दूतावास ने कंबोडिया में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद रह रहे या जबरन गैरकानूनी काम में फंसे नेपाली नागरिकों से तुरंत संपर्क करने की अपील भी की है। इसके लिए नेपाली दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर शिवराज पराजुली (+855 12 215 578), लालसिंह खड्का (+855 93 203 666) और रामजी श्रीकुमार क्षेत्री (+855 96 346 5788) जारी किया है। इसके संपर्क कर प्रभावित नेपाली नागरिक स्वदेश वापसी की प्रक्रिया में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। दूतावास ने यह भी बताया कि कई मामलों में स्कैमिंग केंद्रों में काम करने वाली कंपनियों ने श्रमिकों के पासपोर्ट अपने पास रख लिए हैं या उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते समय दस्तावेज खो गए हैं। ऐसे मामलों में दूतावास बिना शुल्क एकतरफा यात्रा अनुमति पत्र (वन-वे ट्रैवल परमिट) जारी कर नेपाल वापस भेजने की व्यवस्था कर रहा है। दूतावास ने नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे नेपाल सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही रोजगार के लिए विदेश जाएं। जल्दी और अधिक पैसा कमाने के लालच में कंबोडिया, लाओस और म्यांमार जैसे देशों की यात्रा कर अवैध रोजगार में न फंसें।

खाड़ी देशों में रहने वाले 65 हजार से अधिक नेपाली ने वापसी के लिए पंजीकरण कराया

काठमांडू। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष के बीच नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिस पर अब तक कुल 65,886 नेपाली नागरिकों ने वतन वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। नेपाली कूटनीतिक मिशन सरकार के साथ समन्वय कर नेपाली नागरिकों की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल सरकार ने यह ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली खाड़ी देशों में नेपाली दूतावासों के समन्वय में 2 मार्च को शुरू की थी। इसका उद्देश्य क्षेत्र में रह रहे नेपाली नागरिकों की जानकारी एकत्र करना है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापस लाया जा सके। मंत्रालय के अनुसार प्राप्त विवरणों का फिलहाल आकलन और प्रसंस्करण किया जा रहा है, ताकि आगे आवश्यक कदम उठाए जा सकें। इस पोर्टल के माध्यम से नेपाली नागरिक पश्चिम एशियाई देशों में स्थित संबंधित नेपाली दूतावासों के जरिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करा सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल के अनुसार नेपाली मिशनों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-मेल, टेलीफोन या अन्य संचार माध्यमों के जरिए कठिनाई झेल रहे नागरिकों के संपर्क में रहें। मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में रह रहे नेपाली नागरिकों से वर्तमान संकट के दौरान धैर्य बनाए रखने और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले फोटो, वीडियो या ऑडियो सामग्री को रिकॉर्ड या प्रसारित करने से बचने की भी अपील की है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। इससे वहां रह रहे और काम कर रहे हजारों नेपाली नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

ईरान ने युद्ध रोकने के लिए दुनिया के सामने तीन शर्तें रखीं

तेहरान/वाशिंगटन। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का आज 13वां दिन है। ईरान से शुरू यह जंग फारस के खाड़ी देशों तक फैल चुकी है। ईरान और इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से पश्चिम एशिया में हालात और बदतर हो गए हैं। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने युद्ध रोकने के लिए दुनिया के सामने तीन शर्तें रखी हैं। अल जजीरा न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा कि यह तीनों शर्तें बेहद जरूरी हैं। अगर ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दिए जाने, युद्ध के नुकसान की भरपाई करने और भविष्य में हमला न होने की अंतरराष्ट्रीय गारंटी मिल जाए तो ईरान तत्काल प्रभाव से युद्ध रोक देगा। उन्होंने कहा, ईरान के बातचीत की पटरी पर लौटने का यह मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। दूसरी ओर इस युद्ध पर अपना बहुत कुछ गंवा चुके अमेरिका के तेवर अभी भी तल्ख हैं। अमेरिकी मीडिया में प्रसारित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से फिलवक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि युद्ध की लपटें बुझेंगी। ट्रंप ने केंटकी राज्य में एक रैली में कहा कि ईरान जंग में अमेरिका जीत चुका है, लेकिन मिशन पूरा होने तक लड़ाई जारी रहेगी। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने संसद को बताया कि ईरान जंग के शुरुआती छह दिन में अमेरिका ने करीब 11.3 अरब डॉलर (लगभग एक लाख करोड़ रुपये) खर्च कर दिए।

वीओ चिदंबरनार बना डिजिटल प्रतिरूप मंच लागू करने वाला पहला बंदरगाह

एजेंसी, नई दिल्ली

तमिलनाडु का वीओ चिदंबरनार बंदरगाह देश का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जिसने डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लागू किया है। इससे बंदरगाह की अधोसंरचना, परिचालन संपत्तियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की वास्तविक समय की वर्चुअल प्रतिकृति (सटीक रूपरेखा) तैयार होगी, जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी, जहाजों के वापसी के समय में कमी आएगी और ऊर्जा उपयोग का अनुकूलन कर कार्बन उत्सर्जन घटाया जा सकेगा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह पहल बंदरगाह प्रबंधन को स्मार्ट, कुशल और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्घाटन 23 फरवरी को मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था।

डिजिटल प्रतिरूप मंच बंदरगाह की अधोसंरचना, परिचालन संपत्तियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की वास्तविक समय की वर्चुअल प्रतिकृति तैयार करेगा। इससे परिचालन की बेहतर निगरानी, पूर्वानुमान विश्लेषण और डेटा-आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। प्लेटफॉर्म में आईओटी सेंसर, जीपीएस ट्रैकिंग, लाइडार मैपिंग, ड्रोन इमेजिंग और सीसीटीवी नेटवर्क जैसी उन्नत तकनीकों का एकीकरण किया गया है, जिससे बंदरगाह की वास्तविक स्थिति का लगातार आकलन संभव होगा और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

मंत्रालय ने बताया कि यह प्रणाली वास्तविक समय में परिचालन की निगरानी करेगी, जिसमें बर्थ ऑक्यूपेंसी, जहाजों की आवाजाही, क्रेन उपयोग और यार्ड क्षमता का लाइव विजुअलाइजेशन शामिल है।

एआई-आधारित एसेट मॉनिटरिंग से उपकरणों की भविष्यवाणी आधारित देखरेख संभव होगी, जिससे डाउनटाइम कम होगा और परिचालन विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही, जहाजों और माल संचालन की बुद्धिमान शेड्यूलिंग से भीड़भाड़ और प्रतीक्षा समय कम होगा। इस पहल से जहाजों के वापसी जाने के समय में 25 प्रतिशत तक कमी आएगी, उपकरणों की उपलब्धता और विश्वसनीयता बढ़ेगी, परिचालन सुरक्षा मजबूत होगी और ऊर्जा उपयोग का अनुकूलन कर कार्बन उत्सर्जन घटेगा।

बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशांत कुमार पुरोहित ने कहा कि डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन बंदरगाह के आधुनिकीकरण की यात्रा में महत्वपूर्ण कदम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आईओटी और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग कर यह पहल परिचालन दक्षता बढ़ाएगी, जहाजों के टर्नअराउंड समय में सुधार करेगी और सुरक्षा एवं स्थिरता को मजबूत करेगी।

नेपाल को भारत और चीन के बीच पुल का काम करना चाहिए : डॉ. बाबूराम भट्टराई

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. बाबूराम भट्टराई ने भारत और चीन के बीच नेपाल को पुल का काम करने के लिए तैयार रहने की बात कही है। भट्टराई ने नेपाल में उभर रहे जेन-जी और युवा नेतृत्व पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाली युवा देश को समृद्धि की दिशा में आगे ले जाने में पूरी तरह सक्षम हैं।

डॉ. भट्टराई ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे NXT कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री स्तरीय राउंड टेबल सत्र में नेपाल की भू-राजनीतिक स्थिति और युवा नेतृत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अब नेपाल को केवल दो महाशक्ति देशों के बीच की दबाव में फंसे देश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनका तर्क था कि नेपाल को दो उभरती हुई बड़ी शक्तियों के बीच एक गतिशील सेतु (पुल) की भूमिका निभानी चाहिए।

बदलती वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि छोटे देशों के लिए अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना अनिवार्य हो गया है। प्रौद्योगिकी के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे "वसुधैव

कुटुम्बकम्" यानी पूरी दुनिया एक परिवार की अवधारणा को व्यवहार में लागू करना आसान हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और विकास से पर्याप्त लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। उनके अनुसार दक्षिण एशिया में गरीबी और अस्थिरता का मुख्य कारण संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि कमजोर संस्थागत संरचना और शासन की विफलता है। अपने संबोधन में भट्टराई ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशियाई देशों को विकास के लिए आपस में घनिष्ठ सहयोग बढ़ाना चाहिए और वैश्विक साझेदारी के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में नेपाल जैसे देशों के लिए रणनीतिक रूप से स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना ही समझदारी होगी। डॉ. भट्टराई के साथ इस सत्र में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट के मॉरिसन और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री फ्रेडरिक रेनफेल्ड की उपस्थिति रही।

टेम्पल टाउन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत आलंदी को किया जाए शामिल- डॉ. मेधा कुलकर्णी

एजेंसी, नई दिल्ली

राज्य सभा सदस्य डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने टेम्पल टाउन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत आलंदी को शामिल करने की मांग की। गुरुवार को सदन में विशेष उल्लेख के तहत हो रही चर्चा में भाग लेते हुए डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा कि महाराष्ट्र में स्थित मराठी संत ज्ञानेश्वर महाराज की पावन नगरी आलंदी को टेम्पल टाउन डेवलपमेंट फ्रेमवर्कमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि आलंदी देश के सबसे श्रद्धेय तीर्थ स्थलों में से एक है और इसका आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व अत्यंत विशिष्ट है।

यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, विशेषकर आषाढ़ी और कार्तिकी वारी के दौरान, जिससे नागरिक बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यावरणीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक महत्व होने के बावजूद, आलंदी आज भी अनियोजित शहरीकरण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल ही में केंद्रीय बजट में मंदिर नगरों और टियर-II शहरों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर दिया गया जोर इन लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक समयोचित और उपयुक्त नीति

अवसर प्रदान करता है।

इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आलंदी को शामिल करने से तीर्थयात्रियों की सुविधाओं, स्वच्छता, सीवेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट विकास, बाढ़ नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग, सड़क संपर्क और धरोहर संरक्षण में केंद्रित निवेश संभव होगा।

इसके अलावा, आलंदी की पहचान इंद्रायणी नदी से गहराई से जुड़ी हुई है, जिसके लिए त्वरित पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि टेम्पल टाउन का दर्जा मिलने से नदी के पुनर्स्थापन और शहरी विकास के साथ समन्वित योजना बन सकेगी, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और जनस्वास्थ्य सुनिश्चित होगा।

कुवैत के अल-उदैरी बेस पर ईरान का हमला, 100 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल

एजेंसी, तेहरान/कुवैत सिटी

पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष के 13वें दिन ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि कुवैत स्थित अल-उदैरी एयर बेस पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में 100 से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। यह हमला "ट्रू प्रॉमिस 4" ऑपरेशन की 38वीं लहर का हिस्सा था, जिसका कोडनेम "या हैदर अल-कर्रार" रखा गया था। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी और टीवी100 ने बताया कि ईरान के खतम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम ज़ोल्फ़ागरी ने बयान में कहा कि उनकी नेवी ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अभियान चलाया। इसके तहत अल-उदैरी हेलीकॉप्टर बेस पर एक साथ दो भारी मिसाइल

हमले किए गए, जिनके बाद बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। सभी घायल सैनिकों को कुवैत के अल-जबर और अल-मुबारक अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बयान में यह भी दावा किया गया कि बहरीन के मीना सलमान पोर्ट स्थित अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट सैन्य मुख्यालय पर ईरान ने मिसाइल व ड्रोन से हमला किया गया। इसमें उनके कई महत्वपूर्ण सिस्टम और सैन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की बात कही गई है।

आईआरजीसी ने दावा किया कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, इक्विपमेंट वेयरहाउस और अमेरिकी सैनिकों के रहने वाले बैरकों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही कुवैत में मौजूद मुहम्मद अल-अहमद और "अली अल-सलेम" नेवल बेस भी इस हमले से प्रभावित हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक "दुश्मन पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं कर देता।"

इस बीच ईरान की सेना ने यह भी दावा किया कि उसने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन हमलों में निशाना बनाया है। इनमें इजराइली सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस संगठन की यूनिट 8200, ग्रीन पाइन रडार सिस्टम और हाइफा नेवल बेस का मुख्यालय शामिल हैं। इन हमलों से इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि 28 फरवरी से अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल के कब्जे वाले इलाकों और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं।

नेपाल में नई सरकार के लिए विशेषज्ञ मंत्रियों की टीम बनाने में जुटे बालेन्द्र शाह

एजेंसी, काठमांडू

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने नई सरकार गठन को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री पद के दावेदार बालेन्द्र शाह अपनी टीम में मंत्री बनाने को लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। आरएसपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में ही संघीय मंत्रालयों की संख्या कम करने और 'विशेषज्ञ मंत्रियों' की नियुक्ति करने का वादा किया था। अब संसदीय चुनाव में लगभग दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के बाद सवाल उठने लगा है कि पार्टी अपने घोषणापत्र में किए गए इस वादे को कैसे लागू करेगी। हालांकि, घोषणापत्र में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति संघीय संसद के बाहर से की जाएगी, लेकिन इस समय बालेन्द्र शाह की कोर टीम बैठ कर विशेषज्ञों की सूची तैयार कर रही है। इनमें सांसद और गैर सांसद दोनों तरह के लोग शामिल हैं। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(9) के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संघीय संसद के सदस्यों में से समावेशिता सुनिश्चित करते हुए मंत्रिपरिषद का गठन करने का प्रावधान है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री सहित

मंत्रियों की अधिकतम संख्या 25 हो सकती है। इस प्रावधान के तहत मंत्रियों की नियुक्ति मुख्य रूप से नेपाल की संघीय संसद के सदस्यों में से ही की जा सकती है, जिसमें प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा के सदस्य शामिल होते हैं।

हालांकि, संविधान में सीमित अवधि के लिए गैर-सांसद को भी मंत्री नियुक्त करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को शपथ लेने के छह महीने के भीतर संघीय संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई गैर-सांसद मंत्री बनाया जाता है, तो वह अधिकतम छह महीने तक ही पद पर रह सकता है, जब तक कि वह इस अवधि में संसद का सदस्य न बन जाए। काठमांडू-7 से नवनिर्वाचित सांसद और आरएसपी नेता गणेश पराजुली ने कहा कि घोषणापत्र में इस्तेमाल किया गया 'विशेषज्ञ' शब्द पार्टी के भीतर चुने गए योग्य व्यक्तियों को दर्शाता है, न कि बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ का मतलब उस क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति से है। इसका मतलब बाहर से लोगों को लाना नहीं है। वर्तमान संसदीय व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे के तहत संविधान संशोधन के बिना ऐसा संभव भी नहीं है।

पराजुली के अनुसार पार्टी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले सक्षम व्यक्तियों को ही उपयुक्त मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि घोषणापत्र के अनुरूप आरएसपी के नेतृत्व वाली सरकार में बनने वाली नई मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 18 तक सीमित रहने की संभावना है।

एनएचएआई ने जारी किया तमिलनाडु में गंगैकोंडा चोलपुरम बाईपास निर्माण का अनुबंध

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने तमिलनाडु में एनएच-81 के कल्लगम से मीनसुरुट्टी खंड पर गंगैकोंडा चोलपुरम बाईपास के निर्माण के लिए अनुबंध जारी किया है। सात किलोमीटर लंबे इस दो लेन वाले ग्रीनफील्ड बाईपास का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले 11 मार्च को किया था।

एनएचएआई ने बताया कि इस परियोजना में 3.47 किलोमीटर लंबी सेवा सड़कें, दो लघु पुल, दो वीयूपी, तीन एलवीयूपी और आठ बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण शामिल है। बाईपास बनने से गंगैकोंडा चोलपुरम स्थित 1000 वर्ष पुराने बृहदीश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में एनएच-81 मंदिर के बेहद निकट से गुजरता है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा रहता है। बाईपास के निर्माण से भारी वाहनों का यातायात मंदिर

क्षेत्र से हटकर नए मार्ग से गुजरेगा, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

परियोजना से वायु प्रदूषण में कमी आएगी और मंदिर की शिलालेखों पर प्रदूषणजनित क्षति को रोका जा सकेगा। साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही से मंदिर को संभावित नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा यह बाईपास श्रीरंगम स्थित प्रसिद्ध अरंगनाथ स्वामी मंदिर और चिदंबरम के नटराज मंदिर तक यात्रा समय को कम करेगा। परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को निर्बाध यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।

रिपोर्ट- ईरान में अभी सरकार नहीं गिरा पाएगा अमेरिका

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी

अमेरिका और इजराइल लगातार दो हफ्ते से ईरान में एयरस्ट्राइक कर रहे हैं, इसके बावजूद ईरान की सत्ता अभी भी काफी मजबूत है और उसके जल्द गिरने का कोई खतरा नहीं है। यह बात अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आई है। इस मामले से जुड़े तीन सूत्रों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी है। एक सूत्र के मुताबिक कई खुफिया रिपोर्टों में एक जैसा आकलन किया गया है कि ईरान की सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है और वह अभी भी देश की जनता पर कंट्रोल बनाए हुए है। वहीं, तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द जंग खत्म कर सकता है। हालांकि अगर ईरान के कट्टरपंथी नेता सत्ता में बने रहते हैं तो युद्ध खत्म करने का रास्ता निकालना आसान नहीं होगा।

ईरान की मौजूदा सरकार गिरेगी यह तय नहीं: खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वहां की धार्मिक नेतृत्व वाली व्यवस्था अभी भी एकजुट बनी हुई है। इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने भी रॉयटर्स से कहा कि सीक्रेट मीटिंग्स में भी यही बात निकल कर सामने आई है कि फिलहाल ईरान की मौजूदा सरकार गिरने की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों ने यह भी कहा कि जमीन पर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले समय में ईरान के

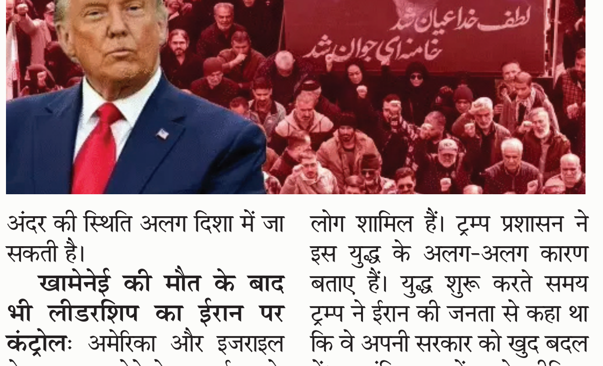

अंदर की स्थिति अलग दिशा में जा सकती है।

खामेनेई की मौत के बाद भी लीडरशिप का ईरान पर कंट्रोल: अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, परमाणु ठिकाने और टॉप लीडरशिप से जुड़े लोग शामिल हैं। ट्रम्प प्रशासन ने इस युद्ध के अलग-अलग कारण बताए हैं। युद्ध शुरू करते समय ट्रम्प ने ईरान की जनता से कहा था कि वे अपनी सरकार को खुद बदल दें। हालांकि बाद में उनके सीनियर अधिकारियों ने कहा कि ईरान की सरकार को हटाना इस ऑपरेशन का मकसद नहीं है। हमलों में खामेनेई के अलावा कई सीनियर अधिकारी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कई बड़े कमांडर भी मारे गए हैं। यह ईरान की एक शक्तिशाली पैरामिलिट्री फोर्स है, जो देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को कंट्रोल करती है। इसके बावजूद अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक खामेनेई और IRGC के अफसरों की मौत के बाद बना 'इंटरनल लीडरशिप सिस्टम' अभी भी देश पर कंट्रोल बनाए हुए है।

ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की एक्सपर्ट सुजैन मलोनी ने कहा कि ईरान के अंदर फिलहाल ऐसी कोई ताकत नहीं है जो सरकार के पास बची हुई शक्ति को चुनौती दे सके। उनके मुताबिक ईरान भले ही अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल न कर पाए, लेकिन देश के अंदर वह अभी भी पूरी तरह कंट्रोल बनाए रखने में सक्षम है।

ईरान में अमेरिकी सैनिक जंग लड़ने जाएंगे यह साफ नहीं: इस हफ्ते ईरान के सीनियर शिया धर्मगुरुओं की संस्था 'असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स' ने खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया है। एक अन्य सूत्र के मुताबिक इजराइल का इरादा यह है कि मौजूदा ईरानी शासन का कोई हिस्सा भी सत्ता में न बचा रहे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि अमेरिका और इजराइल का मौजूदा ऑपरेशन सरकार को कैसे गिरा पाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए संभवतः जमीनी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिससे ईरान के अंदर लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर सकें। ट्रम्प प्रशासन ने अभी तक ईरान में अमेरिकी सैनिक भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया है।

मिडिल ईस्ट की भू-राजनीति में गहराता तनाव- भारत सरकार अलर्ट मोड पर-नागरिकों की सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए तीन मंत्रियों की उच्च स्तरीय संकटकालीन समिति गठितएक्शन शुरू -समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» मिडिल ईस्ट संकट,स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और भारत की ऊर्जा सुरक्षा-वैश्विक भू-राजनीति के बीच रणनीतिक संतुलन की चुनौती

» मिडिल ईस्ट की भू-राजनीति चाहे जिस दिशा में जाए, ऊर्जा सुरक्षा आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की सबसे निर्णायक शक्ति बनी रहेगी- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में ऊर्जा संसाधन केवल आर्थिक विकास का आधार नहीं रहे, बल्कि वे रणनीतिक शक्ति, कूटनीति और भू- राजनीतिक संघर्षों का केंद्र बन चुके हैं। विशेष रूप से पश्चिम एशिया यानें मिडिल ईस्ट क्षेत्र विश्व की ऊर्जा राजनीति का धुरी रहा है। वर्तमान में ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ता सैन्य तनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां इसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनियाँ की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर पड़ रहा है।इसी पृष्ठभूमि में दुनियाँ का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग स्ट्राइट ऑफ़ होर्मूज़ वैश्विक चर्चा के केंद्र में आ गया है।यह जलडमरूमध्य विश्व के तेल व्यापार कीजीवनरेखा माना जाता है। यहां होने वाली किसी भी अस्थिरता का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखाई देता है। हाल के दिनों में इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों,ड्रोन हमलों औरसंभावित खदान बिछाने की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि इसी कारण भारत सहित कई देशों ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को भारत सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। भारत दुनियाँ का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की आपूर्ति बाधा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है।इसी संभावित खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने उच्च स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने स्थिति की निगरानी और संभावित संकट से निपटने के लिए तीन सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है जिसकीअध्यक्षता देश के गृहमंत्री कर रहे हैं। इस समिति में विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री भी शामिल हैं।यह समिति विभिन्न मंत्रालयों और ऊर्जा कंपनियों के साथ मिलकर लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है देश में पेट्रोल, डीज़ल, गैस और एलपीजी की आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में बाधित न हो।पीएम कार्यालय ने भी इस विषय पर सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथियों बात अगर हम ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू आपूर्ति : सरकार की प्राथमिकता को समझने की करें तो भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ लगातार बढ़ रही हैं।औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि और घरेलू उपयोग सभी क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग अत्यधिक है। इस कारण सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि अंतरराष्ट्रीय संकट का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर न्यूनतम हो।तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्याप्त भंडारण बनाए रखें और वितरण व्यवस्था को सुचारु रखें। इसके अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुछ क्षेत्रों में एलपीजी की अस्थायी कमी की खबरें जरूर सामने आई हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ी है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यापक संकट नहीं है बल्कि वितरण व्यवस्था से जुड़ी स्थानीय समस्या हो सकती है।सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है ताकि देशभर में एलपीजी की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा सके। यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत सरकार संभावित संकट से पहले ही तैयारी करना चाहती है। साथियों बात अगर हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वैश्विक ऊर्जा व्यापार की धुरी को समझने की करें तो,दुनियाँ के ऊर्जा मानचित्र में यदि किसी एक समुद्री मार्ग को सबसे अधिक रणनीतिक महत्व प्राप्त है तो वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और यही मार्ग खाड़ी देशों से निकलने वाले तेल और गैस को दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है।भौगोलिक दृष्टि से यह जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है।इसकी चौड़ाई प्रवेश और निकास पर लगभग 50 किलोमीटर है जबकि सबसे संकरे हिस्से में यह लगभग 33 किलोमीटर रह जाती है। इसके बावजूद यह इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी यहां से गुजर सकते हैं।हर महीने लगभग 3000 से अधिक जहाज इस मार्ग से गुजरते हैं और विश्व के लगभग 30 प्रतिशत तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। यही कारण है कि इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का "चोकपॉइंट" कहा जाता है। यदि इस मार्ग में थोड़ी भी बाधा आती है तो तेल की कीमतें तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। साथियों बात अगर हम समुद्री हमले और वैश्विक चिंता को समझने की करें तो हाल के दिनों में इस समुद्री मार्ग में कई संदिग्ध घटनाएं सामने आई हैं। कुछ जहाजों पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले की खबरें आईं, जबकि एक जहाज में आग लगने के बाद उसे खाली कराना पड़ा। इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और ऊर्जा बाजारों को चिंतित कर दिया है।अमेरिकी सैन्य सूत्रों ने दावा किया है कि उन्होंने इस मार्ग में ईरान से जुड़े 16 माइन बिछाने वाले जहाजों को नष्ट कर दिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह क्षेत्र अब एकसंभावित सैन्य संघर्ष का केंद्र बन चुका है।समुद्री मार्गों पर इस तरह की अस्थिरता वैश्विक व्यापार के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि तेल टैंकरों और मालवाहक जहाजों की सुरक्षा सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की स्थिरता से जुड़ी होती है। साथियों बात अगर हम तेल की कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझने की करें तो,ऊर्जा बाजार में अस्थिरता का सबसे बड़ा प्रभाव तेल की कीमतों पर पड़ता है। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं। हाल के दिनों में भी ऐसा ही देखने को मिला है।ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि क्षेत्रीय संघर्ष जारी रहा और ऊर्जा मार्ग अस्थिर बने रहे तो कच्चे तेल की कीमत 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। विशेष रूप से ईरान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि लगातार बमबारी और सैन्य गतिविधियों से क्षेत्रीय सुरक्षा कमजोर हो रही है और इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ना तय है।यदि तेल की कीमतें वास्तव में 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचती हैं तो इसका असर केवल ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। इससे परिवहन, खाद्य उत्पादन, औद्योगिक लागत और वैश्विक व्यापार सभी प्रभावित होंगे। परिणामस्वरूप दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। साथियों बात अगर हम क्या ईरान बंद कर सकता हैस्ट्रेट ऑफ होर्मुज़? इसको समझने की करें तो, यह प्रश्न आज वैश्विक रणनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन चुका है कि क्या ईरान वास्तव में इस जलडमरूमध्य को बंद कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के अनुसार किसी भी देश को अपनी तटरेखा से लगभग12 नॉटिकल मील तक समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण का अधिकार होता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के सबसे संकरे हिस्से में यह मार्ग ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्र के भीतर आता है। इस कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों को इन दोनों देशों के क्षेत्रीय जल से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें ट्रांजिट पैसेज का अधिकार प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि वे इस मार्ग से गुजर सकते हैं।यदि ईरान इस मार्ग को बाधित करना चाहे तो वह समुद्र में माइंस बिछाकर, नौसैनिक गश्त बढ़ाकर या ड्रोन हमलों के जरिए जहाजों को निशाना बना सकता है। हालांकि ऐसा करने पर उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सैन्य जवाबी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। साथियों बात कर हम भारत पर संभावित प्रभाव को समझने की करें तो,यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है तो इसका सबसे बड़ा असर एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भारत, चीन और जापान पर पड़ेगा। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है और इसमें पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण योगदान है।यदि इस मार्ग से तेल की आपूर्ति बाधित होती है तो भारत को न केवल अधिक कीमत पर तेल खरीदना पड़ेगा बल्कि वैकल्पिक स्रोतों की तलाश भी करनी होगी। इससे भारत की ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। परिवहन महंगा होगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और इससे आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।विशेषज्ञों की सलाह और भारत की रणनीतिक दिशाऊर्जा संकट की संभावनाओं को देखते हुए कई विशेषज्ञों और संस्थानों ने भारत सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने सुझाव दिया है कि भारत को घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी रूप से पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए।इसके अलावा रूस जैसे देशों के साथ दीर्घकालिक तेल आपूर्ति समझौते करने की सलाह दी गई है ताकि वैश्विक संकट के समय भी भारत को स्थिर आपूर्ति मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी ऊर्जा नीति में अधिक रणनीतिक स्वायत्तता अपनानी चाहिए और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। <अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति का नया युग शुरू मिडिल ईस्ट में चल रहा संकट केवल एकक्षेत्रीय संघर्ष नहीं है बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की नाजुकता को उजागर करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे रणनीतिक मार्गों पर निर्भरता ने दुनिया को यह एहसास दिलाया है कि ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा पहले से तैयारी करना, भंडारण बढ़ाना, वैकल्पिक स्रोत तलाशना और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है।वर्तमान संकट यह भी संकेत देता है कि भविष्य की ऊर्जा नीति केवल आयात पर निर्भर नहीं रह सकती। नवीकरणीय ऊर्जा, सामरिक भंडारण और बहु-स्रोत आपूर्ति जैसे उपाय ही भारत को वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता से सुरक्षित रख सकते हैं।मिडिल ईस्ट की भू-राजनीति चाहे जिस दिशा में जाए, एक बात स्पष्ट है ऊर्जा सुरक्षा आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की सबसे निर्णायक शक्ति बनी रहेगी। और इसी चुनौती के बीच भारत को अपनी रणनीतिक दूरदृष्टि और संतुलित कूटनीति के साथ आगे बढ़ना होगा।

-संकलनकर्ता लेखक
- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार
साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक
चिंतक कवि संगीत माध्यमा
सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन
सनमुखदास भावनानी गोंदिया
महाराष्ट्र 9284141425

जलियांवाला बाग से कैक्सटन हॉल तक : शहीद-ए-आजम ऊधम सिंह की अमर गाथा

लेखक- -सुनील कुमार महला

शहीद-ए-आजम सरदार उधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन दीपस्तंभों में से एक हैं, जिनका नाम साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो उधम सिंह (राम मोहम्मद सिंह आज़ाद) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके बचपन का नाम शेर सिंह था तथा उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को सुनाम,जिला संगरूर,पंजाब में हुआ था।उनके पिता का नाम सरदार टहल सिंह था, जो रेलवे ओवरसियर (चौकीदार) के रूप में कार्य करते थे तथा उनकी माता का नाम नारायण कौर था।पाठकों को बताता चलूं कि बचपन में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया था, कहते हैं कि उनका पालन-पोषण अमृतसर के एक अनाथालय में हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार माता-पिता के साये के बिना, उन्हें और उनके बड़े भाई (मुक्ता सिंह) को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी।यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अनाथालय में ही रहकर पूरी की और वहीं से 1918 में मैट्रिक की परीक्षा पास की।13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए भीषण जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने उधमसिंह के जीवन की दिशा बदल दी। दरअसल, उस समय वे अमृतसर में ही थे, और कहा जाता है कि वे घायल लोगों को पानी पिला रहे थे। इस क्रूर घटना ने उनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने का संकल्प लिया। वे इस घटना के लिए पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर को जिम्मेदार मानते थे।

जलियांवाला बाग हत्याकांड पृष्ठभूमिः- दरअसल, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट अधिनियम-1919 (जिसे काला कानून भी कहा गया) पारित किया। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी।इस अन्यायपूर्ण कानून का पूरे देश में विरोध हुआ। इसी विरोध के दौरान अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिहाई की मांग और रॉलेट एक्ट(अधिनियम) के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई।

वैशाखी का दिन और विशाल भीड़ः- 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का पर्व था। इसलिए लगभग 10,000 पुरुष, महिलाएँ और बच्चे जलियांवाला बाग में एकत्र हो गए थे। कई लोग राजनीतिक सभा के लिए आए थे, जबकि अनेक लोग केवल मेले के कारण वहाँ पहुँचे थे। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि उस समय जलियांवाला बाग कोई व्यवस्थित बगीचा नहीं था, बल्कि यह मकानों से घिरा एक बड़ा खाली मैदान था तथा वहाँ आने-जाने के लिए केवल एक संकरा प्रवेश मार्ग था और चारों ओर ऊँची दीवारें व मकान स्थित थे।जब इस विशाल सभा की सूचना ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर को मिली, तो वह लगभग 90 सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा। कहते हैं कि उसके साथ दो मशीनगनों से लैस बख्तरबंद गाड़ियाँ भी थीं, लेकिन बाग का रास्ता संकरा होने के कारण वे अंदर नहीं जा सकीं।

गोलाबारी और भीषण नरसंहारः- जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की और लगभग 1650 राउंड गोलियाँ चलाईं।गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक गोला-बारूद लगभग समाप्त नहीं हो गया। चूँकि, सैनिकों ने सभी रास्तों को घेर लिया था, इसलिए लोग वहाँ से भाग नहीं सके और सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े।अपनी जान बचाने के लिए कई लोग बाग में स्थित एक कुएँ में कूद गए। बाद में उस कुएँ से 100 से अधिक शव निकाले गए। आज यह स्थान शहीदी कुआँ के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा गया है।

हालांकि स्पीकर ओएम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हार गया, लेकिन विपक्ष को उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहार का मुद्दा उठाने का अवसर मिल गया

लोकतंत्र की शान

अंततः, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के मुखर घटक दलों के सांसदों द्वारा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव, जैसा कि अपेक्षित था, लोकसभा में पराजित हो गया। यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान काफी तीखी बहस और कटु दृश्य देखने को मिले, लेकिन विपक्ष को कम से कम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने और अपनी चिंता व्यक्त करने का अवसर मिला कि किस प्रकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सत्ताधारी दल और अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है और किस प्रकार अध्यक्ष होने के बावजूद, जो संवैधानिक रूप से लोकसभा के एक निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती प्रमुख हैं और देश के लाखों मतदाताओं द्वारा चुने गए हैं, उन पर पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। विपक्ष के अनुसार, यह पहली बार है कि लोकसभा अध्यक्ष निचले सदन के संवैधानिक प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि के रूप में पूर्णतया पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ी रही, वहीं गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जमकर मजाक उड़ाते हुए सदन को याद दिला रहे थे कि कैसे उन्होंने आंखें झपकाकर, प्रधानमंत्री के पास जाकर, उन्हें गले लगाकर और यहां तक कि फ्लाइंग किस देकर सदन में हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी। इस पर पूरे विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस सांसदों ने अमित शाह और सत्ता पक्ष के सांसदों पर खड़े होकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। इसके परिणामस्वरूप विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में तीखी बहस छिड़ गई, जिसके चलते अविश्वास प्रस्ताव पर ध्वनि मत से मतदान करना पड़ा। हालांकि शुरू से ही यह स्पष्ट था कि अविश्वास प्रस्ताव विफल हो जाएगा, लेकिन इससे विपक्ष को स्पीकर के पक्षपातपूर्ण रवैये (सरकार समर्थक) को उठाने का मौका मिल गया, जबकि संवैधानिक रूप से स्पीकर को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। इससे पहले कई स्पीकर, विशेषकर सोमनाथ चटर्जी जैसे, ने संसदीय कार्यवाही में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि संसद सर्वोच्च है। ध्वनि मत के दौरान विपक्ष के पास सत्ताधारी दलों की तुलना में पहले से ही कम वोट थे। भारतीय विपक्ष के पास केवल 238 वोट थे, जिनमें कांग्रेस के 99 सांसद और बाकी समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य क्षेत्रीय दलों के सांसद शामिल थे। दूसरी ओर, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 293 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, जिनमें अकेले भाजपा के 240 सांसद, जेडीयू के 16, टीडीपी के 12 और अन्य एनडीए दलों के सांसद शामिल थे। अब सवाल उठता है कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को हारने की आशंका के बावजूद क्यों पेश किया? इसका कारण यह था कि विपक्षी दलों के अनुसार, वर्तमान अध्यक्ष स्पष्ट रूप से पक्षपाती थे और सत्ताधारी दल का पक्ष ले रहे थे, तथा विपक्ष के विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, उन्हें संसद में बोलने नहीं दे रहे थे और यहां तक कि उन्हें सदन से निष्कासित भी कर रहे थे। लोकसभा में पूर्व जनरल नरवणे की किताब पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा आवाज उठाने की घटना सर्वविदित है, जब उन्हें यह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई और अंततः सदन से निलंबित कर दिया गया। सरकार की आलोचना करने वाले राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने के लिए कई सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। विपक्ष ने प्रधानमंत्री की सीट का महिलाओं द्वारा घेराव करने का मुद्दा भी उठाया था, हालांकि प्रधानमंत्री उस समय सीट पर नहीं थे। भाजपा ने महिला सांसदों पर प्रधानमंत्री के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया था। अपने भाषण की शुरुआत में कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई ने कहा था कि यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के प्रति निष्पक्ष रवैया छोड़ दिया है और पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि स्पीकर स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं और विपक्षी सांसदों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें ऐसे निर्णय सुनाना भी शामिल है जो विपक्ष के बोलने और मुद्दे उठाने के अधिकार को कमजोर करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर विवादास्पद मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की बजाय खुले तौर पर सत्ताधारी पार्टी का पक्ष लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि स्पीकर के चुनाव के समय सभी ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष नैतिकता का झूठा दिखावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके व्यवहार ने ही स्पीकर को यह प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, हालांकि उनसे असहमति हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज भी स्पीकर की सुरक्षा उनके कक्ष में खतरे में रहती है। विपक्षी सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया और सदन के well में आ गए।

तिरुचिरापल्ली से नई रेल क्रांति का उदघोष

लेखक- बिनोद कुमार सिंह

दक्षिण,दक्कन और पूर्वी भारत को जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम,रेल सेवाओं तक सीमित नहीं रहा। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 5,650 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजना ओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इनमें रेलवे,ऊर्जा,पेट्रोलियम अवसंरचना,ग्रामीण सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं। भारतीय रेल केवल पटरियों पर दौड़ती हुई धातु की गाड़ियाँ नहीं है। वह भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक संपर्क का सबसे बड़ा सेतु है। इस विशाल देश में जहाँ भौगोलिक दूरियाँ अनेक बार लोगों, बाजारों और अवसरों के बीच दूरी पैदा कर देती हैं,वहाँ रेल व्यवस्था उन्हें जोड़ने वाली जीवनरेखा का कार्य करती है। जब भी कोई नई रेल सेवा शुरू होती है,तो वह केवल एक परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं होती,बल्कि लाखों लोगों के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। तमिलनाडु के ऐतिहासिक नगर तिरुचिरापल्ली ने आज ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षण देखा,जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस,दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही केरल के एर्णाकुलम से एक और पैसेंजर ट्रेन सेवा भी शुरू की गई। इन रेल सेवाओं के आरंभ के साथ दक्षिण भारत,दक्कन और पूर्वी भारत के बीच संपर्क का एक नया अध्याय खुल गया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का महत्व केवल रेल सेवाओं तक सीमित नहीं रहा। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 5,650 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं में रेलवे, ऊर्जा,पेट्रोलियम अवसंरचना, ग्रामीण सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं। यह पूरा कार्यक्रम इस बात का संकेत देता है कि आधुनिक भारत का विकास अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रह सकता,बल्कि उसे देश के हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुँचना होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेल केवल परिवहन का साधन नहीं है,बल्कि यह देश की प्रगति और सामाजिक एकता की महत्वपूर्ण धुरी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पिछले वर्षों में रेलवे के व्यापक आधुनिकीकरण, नई ट्रेनों की शुरुआत,स्टेशन पुनर्विकास और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण जैसे कदमों ने यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की है। उनके अनुसार विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश के छोटे-छोटे शहर और कस्बे भी मजबूत परिवहन नेटवर्क से जुड़ेंगे। इस संदर्भ में पोदानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दक्षिण भारत का औद्योगिक शहर कोयंबटूर लंबे समय से देश के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में गिना जाता है। कपड़ा उद्योग,मशीन टूल्स,पंप निर्माण और छोटे-मध्यम उद्योगों की विशाल श्रृंखला ने इस शहर को दक्षिण भारत की औद्योगिक राजधानी जैसा स्थान दिलाया है। यहाँ के कारखानों की मशीनों की निरंतर आवाज़ केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है, बल्कि यह भारत के औद्योगिक तंत्र की धड़कन भी है। फिर भी एक विडंबना लंबे समय से बनी हुई थी कि इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद कोयंबटूर का पूर्वी भारत के खनिज और ऊर्जा क्षेत्र से सीधा रेल संपर्क नहीं था। अब यह स्थिति बदल गई है। पोदानूर से धनबाद तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस पहली बार दक्षिण भारत के इस औद्योगिक क्षेत्र को झारखंड के कोयला और इस्पात क्षेत्र से सीधे जोड़ती है। पोदानूर जंक्शन कोयंबटूर का दूसरा प्रमुख रेलवे केंद्र है और यही इस नई ट्रेन का प्रारंभिक स्टेशन है। इसके कुछ ही समय बाद यह कोयंबटूर जंक्शन पहुँचती है, जिससे यात्रियों को इस सेवा का लाभ लेने के लिए दो प्रमुख स्टेशन उपलब्ध हो जाते हैं। पहले कोयंबटूर या तिरुप्पुर से झारखंड और पूर्वी भारत जाने वाले यात्रियों को चेन्नई,विजयवाड़ा या अन्य बड़े जंक्शनों पर ट्रेन बदलनी पड़ती थी। इससे यात्रा लंबी,जटिल और थकाऊ हो जाती थी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस इस व्यवस्था को सरल और सुगम बनाती है। यह ट्रेन अपने मार्ग में सेलम, रेनिगुंटा,विजयवाड़ा,झारसुगुड़ा और राँची जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरती है। इस प्रकार यह रेल सेवा केवल दो शहरों को नहीं जोड़ती,बल्कि दक्षिण भारत के औद्योगिक गलियारे और पूर्वी भारत की ऊर्जा पट्टी के बीच एक नया आर्थिक सेतु स्थापित करती है। कोयंबटूर और तिरुप्पुर की पहचान केवल उद्योगों से नहीं है। यह क्षेत्र देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों का भी प्रमुख केंद्र है। झारखंड,बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से हजारों युवा रोज़गार की तलाश में यहाँ आते हैं और करघों,कारखानों तथा निर्माण स्थलों पर काम करते हैं।

हार्दिक के खिलाफ तिरंगे के अपमान की शिकायत

वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान फ्लैग ओढ़कर जमीन पर लेटने का आरोप

अहमदाबाद (एजेंसी)। क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के खिलाफ तिरंगे के अपमान को लेकर बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर ने यह शिकायत की है। टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद अहमदाबाद में जश्न के दौरान पंड्या पर तिरंगे का सम्मान न करने का आरोप लगाया गया है।

वायरल वीडियो के आधार पर शिकायत- शिकायतकर्ता के अनुसार, टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर जश्न मनाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक वीडियो में पंड्या अपने कंधे पर तिरंगा ओढ़कर मैदान पर नाचते और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि जश्न के दौरान पंड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मंच पर लेटे दिखे। उस समय भी उनके कंधे पर तिरंगा था। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ है।

राष्ट्रीय ध्वज कानून का हवाला

वकील वाजिद खान ने कहा कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टु नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के अनुसार तिरंगे की गरिमा बनाए रखना अनिवार्य है। उनका आरोप है कि जश्न के दौरान हार्दिक पंड्या इस बात का ध्यान नहीं रख पाए, जिसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जा सकता है। इस मामले में उन्होंने इसी कानून की धारा 2 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। यह कानून राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत तिरंगे को जमीन पर गिरने देना, उसे अनुचित तरीके से पहनना या किसी भी तरह उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना दंडनीय माना जाता है। खान ने बताया कि उन्होंने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। शुरुआत में पुलिस ने कहा कि घटना अहमदाबाद में हुई है, इसलिए मामला वहीं दर्ज होना चाहिए। हालांकि, खान ने तर्क दिया कि तिरंगा पूरे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसलिए इसकी शिकायत कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है। बाद में पुलिस ने उनकी शिकायत स्वीकार कर ली और उसकी कॉपी भी उन्हें दे दी।

क्रिकेटर कुलदीप की शादी में होगी 20 हजार की थाली

शादी का कार्ड राधा-कृष्ण थीम पर, सुनहरी नक्काशी में दिखी रजवाड़े जैसी झलक

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी करने जा रहे हैं। शादी में शामिल होने के लिए कानपुर

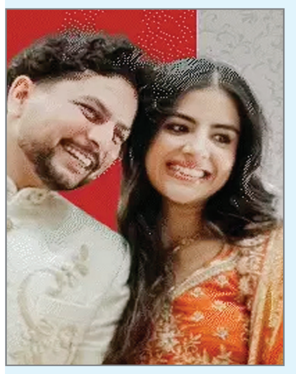

से परिवार और रिश्तेदार मसूरी रवाना हो चुके हैं। यह शादी 14 मार्च (शनिवार) को मसूरी के आलीशान 'वेलकम होटल द सेवॉय' में होगी। इसके तीन दिन बाद यानी 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी आयोजित की जाएगी। कुलदीप और वंशिका ने 4 जून 2025 को लखनऊ में सगाई की थी। इस शादी का बजट 2 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। कुलदीप और वंशिका की शादी का खूबसूरत और शाही वेडिंग कार्ड भी सामने आया है।

गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड देगा बीसीसीआई

- द्रविड़ को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा
- 19 वर्ल्डकप जिताने वाले म्हात्रे भी सम्मानित होंगे

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। वहीं, टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और हेड कोच राहुल द्रविड़ को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। मीडिया के मुताबिक, 15 मार्च को दिल्ली में बीसीसीआई एनुअल अवॉर्ड प्रोग्राम होगा।

इसके अलावा, आयुष म्हात्रे को लाला अमरनाथ अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। म्हात्रे की कप्तानी में भारत इसी साल की शुरुआत में अंडर-19 वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। राहुल द्रविड़ के अलावा मिताली राज को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से नवाजा जाएगा।

इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मुंबई एसोसिएशन को बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन का पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि अब तक इसे लेकर बीसीसीआई के तरफ से कोई ऑफिशियन बयान नहीं आया है।

- **गिल पिछले साल तीनों फॉर्मेट के टॉप स्कोरर**- साल 2025 में भारतीय कप्तान गिल का प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 983 रन बनाए, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज में 70 से ज्यादा की औसत से बनाए गए 754 रन शामिल थे। वनडे में भी गिल ने 490 रन बनाए और भारत के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई। कुल मिलाकर उन्होंने सभी फॉर्मेट में 49 की औसत से 1764 रन बनाए, जिसमें सात शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे।
- **द्रविड़ ने भारत को 2024 में टी-20 वर्ल्ड चैंपियन बनाया**-द्रविड़ को टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है, उन्होंने टेस्ट में 13,288 और वनडे में 10,889 रन बनाए। कोच के रूप में उनके कार्यकाल में भारत ने आईसीसी टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची और 2024 का टी-20 वर्ल्ड कप 2024 भी जीता।

शतरंज का नन्हा जादूगर

दुनिया का नंबर-1 खिलाड़ी

- तमिज अमुधन 2000 ईलो रेटिंग पार करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी, आठ साल की उम्र में जीती कार

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के तमिज अमुधन इस समय विश्व शतरंज जगत में चर्चा का केंद्र है। मात्र 9 साल की उम्र में तमिज न केवल अंडर-9 कैटेगरी में दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी बन गए हैं, बल्कि वे इस उम्र में 2000 ईलो रेटिंग पार करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। तमिज ने महज चार साल की उम्र में चचेरे भाइयों को देखकर शतरंज सीखना शुरू किया था। उनके भीतर खेल की सहज समझ इतनी गहरी थी कि एक जिला स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान कल्लाकुरिची के एक बस ड्राइवर रविचंद्रन की नजर उन पर पड़ी। रविचंद्रन पार्ट-टाइम शतरंज कोचिंग भी देते थे। उन्होंने देखा कि बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के भी इस छोटे से बच्चे ने अनुभवी खिलाड़ियों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया।

एथेंस ऑफ द ईस्ट शतरंज टूर्नामेंट में रविचंद्रन ने सिल्वर मेडल जीता

रविचंद्रन ने तमिज की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें मुफ्त में कोचिंग देने का फैसला किया। इसके बाद तमिज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 साल की उम्र में उन्होंने स्टेट अंडर-9 टूर्नामेंट में 9 में से 9 अंक हासिल कर सबको

हैरान कर दिया। यह उनके करियर का पहला बड़ा 'ब्रेक' था। तमिज के करियर का सबसे यादगार पल पिछले साल आया। 'एथेंस ऑफ द ईस्ट' शतरंज टूर्नामेंट में उन्होंने ?सिल्वर मेडल जीता। पुरस्कार के रूप में इस 8 साल के बच्चे को कार दी गई। किसी भी एथलीट के लिए इतनी कम उम्र में ऐसा पुरस्कार जीतना एक दुर्लभ उपलब्धि है।

तमिज की इस सफलता के पीछे उनके माता-पिता का असाधारण बलिदान है। पिता सरकारी नौकरी में हैं और साधारण कृषि पृष्ठभूमि से आते हैं। तमिज की बेहतर ट्रेनिंग के लिए परिवार ने एक कठिन फैसला लिया। तमिज की मां उनके साथ 350 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में रहती हैं ताकि ट्रेनिंग बाधित न हो। वहीं, पिता घर पर 10 साल की बेटी उथिशा के साथ रहते हैं। तमिज के पिता स्वीकार करते हैं कि शतरंज महंगा खेल है। यात्रा, रहने, एंट्री फीस और कोचिंग का खर्च उठाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। तमिज के पिता का कहना है कि अगर उन्हें पहले पता होता कि इस क्षेत्र में इतना खर्च आता है, तो शायद वे इस खेल को नहीं चुनते। लेकिन अब जब वह नंबर-1 खिलाड़ी है, तो हम उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। तमिज की इस यात्रा को जारी रखने के लिए अब उन्हें किसी बड़े प्रायोजक की जरूरत है। आर्थिक तंगी के कारण वे कई बार नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे।

पिता के निधन के बाद जितेश की बदली सोच

- **बोले-** वर्ल्डकप टीम से बाहर होने का दुख छोटा लगा, मैं फिनिशर बनने को तैयार

नईदिल्ली (एजेंसी)। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने कहा कि टी-20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने से उन्हें निराशा जरूर हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके जीवन में ऐसा व्यक्तिगत दुख आया जिसने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी।

जितेश के पिता मोहन शर्मा का 1 फरवरी को छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने बताया कि उस समय वह सात दिन तक अपने पिता के साथ रहे और उसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि परिवार उनके लिए वर्ल्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था।

मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जितेश ने अपने करियर के उतार-चढ़ाव और निजी जिंदगी पर खुलकर बात की।

जितेश बोले-

- **वर्ल्ड कप से ज्यादा मेरे पिता को मेरी जरूरत थी**- वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के अनुभव पर जितेश ने कहा,जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा निराश था। आखिर मैं भी एक इंसान हूं और बुरा महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ही समय बाद मेरे पिता बीमार हो गए और 1 फरवरी को उनका निधन हो गया। मैं उनके आखिरी सात दिनों में उनके साथ था। तब मुझे अहसास हुआ कि मेरे पिता को वर्ल्ड कप से ज्यादा मेरी जरूरत थी। उसके बाद मेरे मन में टीम से बाहर होने का कोई दुख नहीं रहा।

क्रिकेट सीखी मजबूती

जितेश का कहना है कि क्रिकेट ने उन्हें इस दुख के साथ आगे बढ़ना सिखाया है। उन्होंने कहा,अगर मेरे पिता आज जिंदा होते तो वह मुझे यही कहते कि जाओ और अभ्यास करो, मेरे बारे में चिंता मत करो। इसलिए जब भी मैं दुखी होता हूं, यही सोचता हूं कि वह मुझे खेलने और आगे बढ़ने की सलाह देते।

रिंकू सिंह से ली प्रेरणा

जितेश ने अपने साथी खिलाड़ी रिंकू सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि निजी मुश्किलों के बाद मैदान पर लौटना बहुत बड़ी बात होती है।

विराट कोहली से मिलती है प्रेरणा

जितेश ने बताया कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ रहते हुए उन्हें विराट कोहली को करीब से देखने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें काफी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि कोहली की तैयारी,अनुशासन और ऊर्जा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ छोटी-छोटी चीजें देखकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जिस तरह विराट अपना दिन शुरू करते हैं और तैयारी करते हैं, वह बहुत प्रेरणादायक है। हालांकि 32 साल की उम्र में भी मैं उनकी ऊर्जा की बराबरी नहीं कर सकता।

घर के बड़े बेटे की जिम्मेदारी

- **परिवार के सामने कमजोर नहीं हो सकता**- पिता के जाने के बाद जितेश अब अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा,जब आप अपने पिता को खो देते हैं, तब आपको समझ आता है कि अब परिवार के फैसले लेने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे अपनी मां और भाई का ख्याल रखना है। मैं उनके सामने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर सकता और न ही कमजोर दिख सकता हूं, क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो वे मुझे ही देख रहे होते हैं।

व्यापार

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका ने कर दिया बड़ा ऐलान

नईदिल्ली, एजेंसी। ईरान-इजरायल युद्ध के बीच एक राहतभरी खबर आ रही है। खबर पेरिस से है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा। ईरान-इजरायल युद्ध के बीच एक राहतभरी खबर आ रही है। खबर पेरिस से है। अमेरिकी

ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने घोषणा की है कि अमेरिका अपने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करेगा। यह कदम ईरान युद्ध के कारण बढ़ती तेल कीमतों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रयासों के हिस्से के रूप में उठाया गया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एपी ने दी है। राइट ने बताया कि यह जारी करने की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होगी और प्लांड विड्राल रेट के अनुसार इसे पूरा होने में लगभग 120 दिन लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अगले एक वर्ष के भीतर लगभग 200 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई करेगा। पिछले महीने के अंत तक अमेरिका के स्ट्रेटजिक रिजर्व में 415 मिलियन बैरल से अधिक तेल था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रिजर्व ऑयल के उपयोग के महत्व को कम करके आंका था, लेकिन बुधवार को पुष्टि की कि उनका प्रशासन 'इसे थोड़ा कम करेगा' और फिर इसे भर देगा। पेरिस स्थित के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने कहा, 'यह बाजारों में रुकावट के तत्काल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्रवाई है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल और गैस के स्थिर प्रवाह में वापसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होर्मुज स्ट्रेट के जरिए फिर से शुरू होना है। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में फारस की खाड़ी में कमर्शियल जहाजों पर हमले किए हैं। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और होर्मुज में कार्गो यातायात प्रभावी रूप से रुक गया है। इस स्ट्रेट से फारस की खाड़ी से हिंद महासागर की ओर लगभग पांचवां हिस्सा तेल भेजा जाता है।

सोने-चांदी के भाव में दूसरे दिन भी गिरावट

- तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है

नईदिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। वहीं, मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इन दोनों वजहों ने मिलकर सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है।

सुबह 9:15 बजे के आसपास एमसीएक्स पर सोना अप्रैल वायदा 0.10 प्रतिशत गिरकर 1,61,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। उस समय एमसीएक्स चांदी मई वायदा 0.57 प्रतिशत गिरकर 2,66,969 प्रति किलोग्राम पर थी। दूसरी ओर ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिंगापुर में सुबह 8:05 बजे सोने की कीमत (स्पॉट गोल्ड) 0.9 प्रतिशत गिरकर 5,132.76 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, चांदी 1.5 प्रतिशत गिरकर 84.44 डॉलर पर आ गई। दूसरी ओर, प्लैटिनम में 1 प्रतिशत और पैलेडियम में 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स भी 0.2 प्रतिशत की मजबूती के साथ बढ़त पर रहा। हालांकि, साल की शुरुआत में अमेरिका का मुख्य महंगाई आंकड़ा नियंत्रित दिख रहा था, लेकिन अब भविष्य को लेकर बढ़ती महंगाई की आशंकाओं ने फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में कटौती की संभावना को कम कर दिया है। इस उम्मीद से डॉलर को मजबूती मिली है और डॉलर इंडेक्स में 0.3 प्रतिशत की बढ़त देखी गई। वहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी आगाह किया है कि इस साल उसकी महंगाई दर 3 प्रतिशत के पार जा सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई की चिंता और गहरा गई है।

कभी 119 का था वोडाफोन आइडिया का शेयर, आज 10 से भी कम है भाव, कंपनी लेकर आ रही नया प्लान

नईदिल्ली, एजेंसी। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गुरुवार, 12 मार्च को करीब 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह शेयर कभी करीब 119 रुपये का था। आज शेयरों में यह गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में आई भारी कमी के कारण आई है। इस बीच कंपनी ने अगले हफ्ते संस्थागत निवेशकों से मुलाकात करने की योजना बनाई है, जिसे नई फंडिंग जुटाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसई पर कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 3.7 प्रतिशत गिरकर 9.71 रुपये के पिछले बंद भाव से 9.35 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। बता दें 17 अप्रैल 2015 को आइडिया के शेयर 118.96 रुपये के थे और अब 9.65 रुपये के आज के निचले स्तर पर आ गया था। टेलीकॉम कंपनी ने 11 मार्च को शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि वह 16 मार्च को सिंगापुर और 17 मार्च को हांगकांग में संस्थागत निवेशकों से मिलेंगी। हालांकि, कंपनी ने इन एक-एक और समूह बैठकों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि वह नए फंड जुटाने की संभावनाएं तलाश सकती है। इससे पहले जनवरी में, कंपनी ने अपनी 2.0 रणनीति के तहत 45,000 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय योजना का अनावरण किया था। कंपनी का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में दोहरे अंकों में रेवेन्यू ग्रोथ, आपरेशनल लाभ में तीन गुना वृद्धि और लगातार ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हासिल करना है। मिंट की

रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी पूंजीगत व्यय योजना के सपोर्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपये की बैंक फंडिंग और 10,000 करोड़ रुपये की नॉन-फंड सुविधाएं जुटाने की योजना बना रहा है। कंपनी का कहना है कि 45,000 करोड़ रुपये का यह प्रस्तावित निवेश, पिछले छह तिमाहियों में खर्च किए गए 18,000 करोड़ रुपये के साथ मिलकर, साढ़े चार साल की अवधि में कंपनी के कुल नेटवर्क निवेश को 60,000 करोड़ रुपये से अधिक कर देगा। इस बीच, वोडाफोन आइडिया ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही के दौरान एक सहायक कंपनी के माध्यम से नॉन-कनवर्टेबल डिबेंचर के जरिए 3,300 करोड़ रुपये जुटाए। 27 जनवरी को जारी कंपनी के बयान के अनुसार, 31 दिसंबर तक टेलीकॉम कंपनी पर बैंकों का लगभग 1,126 करोड़ रुपये बकाया था। इसी अवधि में इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, मासिक स्तर पर देखें तो फरवरी में 5 प्रतिशत गिरावट के बाद मार्च में अब तक स्टॉक में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है। स्टॉक ने पिछले साल 14 अगस्त को 6.12 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर को छूने के बाद, 31 दिसंबर को 12.80 रुपये का 52-सप्ताह का उच्च स्तर बनाया था।

दक्षिण भारत के रेस्टोरेंट ने 'डोसा' को कर दिया बाय-बाय, अब 'सैंडविच' से दोस्ती

बेंगलुरु, एजेंसी। डोसा, इडली और वड़ा के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध है। वहां आप चाहे किसी बड़े शहर में चले जाएं या छोटे शहर या कस्बे में। वहां हर जगह आपको बड़े रेस्टोरेंट से लेकर सड़क किनारे के ठेले पर ये व्यंजन मिल जाएंगे। लेकिन एलपीजी सिलेंडर के संकट के बीच रेस्टोरेंट से ये व्यंजन गायब हो रहे हैं। इसके बदले आपको पावरोटी या ब्रेड पर आधारित व्यंजन मिलेंगे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक बेंगलुरु के रेस्टोरेंट ने तो गजब का जुगाड़ ढूंढा है। शहर के कई टॉप रेस्टोरेंट ने वड़ा और डोसा जैसे व्यंजनों को मेनू से निकाल दिया है। अब वे सैंडविच और पावरोटी से बनने वाले अन्य खाद्य पदार्थों को प्रोमोट कर रहे हैं। ताकि इसे बनाने में गैस सिलेंडर की जरूरत न के बराबर रहे।

बेंगलुरु के दिल कहे जाने वाले मजेस्टिक एरिया में पड़ता है गांधी नगर। वहां के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, द्वार पर ही एक नोटिस चिपका हुआ है। इसमें लिखा हुआ है- डियर गेस्ट्स। खाड़ी देशों के संकट की वजह से पूरे शहर में गैस की आपूर्ति बाधित है। इसलिए इस समय आपको पूरा मेनू नहीं मिलेगा। हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे सहयोग की अपेक्षा है। इस समय कुछ रेस्टोरेंट में आप गैस से चलने वाली भट्ठियों के बदले प्लाइवुड के टुकड़ों और लकड़ी के कोयले से चलने वाली भट्ठी देखेंगे। ऊपर से इन ईंधन की आपूर्ति सीमित है। इसलिए वे ऐसे व्यंजन बना रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)